हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

वार्षिक योजना बजट

2026–27

के लिए

मानननीय विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु
दिनांक 06 तथा 07 फरवरी, 2026 को
माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में
आयोजित बैठकों की कार्यवाही ।

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002

विषय सूची

क. सं. / जिला	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	पृष्ठ
1.	2.	3.
प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, के स्वागत भाषण का संक्षिप्त विवरण ।		1
	1. ऊना	
1.	चिन्तपूर्णी	1–2
2.	गगरेट	2
3.	ऊना	3
4.	कुटलैहड़	3–4
	2. हमीरपुर	
1.	भोरंज	4
2.	सुजानपुर	5
3.	बड़सर	5–6
	3. सिरमौर	
1.	पच्छाद	6–7
2.	नाहन	7
3.	श्री रेणुका जी	8
4.	पावंटा साहिब	8–9
	4. सोलन	
1.	अर्की	9
2.	नालागढ़	10
3.	दून	10–11
4.	कसौली	11–12

5. चम्बा		
1.	चुराह	12
2.	भरमौर	12
3.	चम्बा	12–13
4.	डलहौजी	13–14
6. बिलासपुर		
1.	झण्डूता	14
2.	बिलासपुर	14–15
3.	श्री नैनादेवी जी	15–16
7. लाहौल–स्पिती		
1.	लाहौल–स्पिती	16–17
8. कुल्लू		
1.	मनाली	17–18
2.	कुल्लू	18
3.	बंजार	18
4.	आनी	18–19
9. मण्डी		
1.	करसोग	19
2.	सुन्दरनगर	19–20
3.	नाचन	20
4.	द्रंग	20–21
5.	जोगिन्द्रनगर	21
6.	धर्मपुर	21–22
7.	मण्डी	22–23

8.	बल्ह	23–25
9.	सरकाघाट	25
	10. शिमला	
1.	चौपाल	25–26
2.	रोहड़ू	26–28
3.	शिमला (शहरी)	28
	11. काँगड़ा	
1.	नूरपुर	28
2.	इन्दौरा	28–30
3.	जसवां–प्रागपुर	30–31
4.	ज्वालामुखी	31
5.	सुलह	31–32
6.	कांगड़ा	32
7.	पालमपुर	32–33
8.	बैजनाथ	33
9.	नगरोटा बगवां	33–34
मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार, का धन्यवाद प्रस्ताव ।		34
माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश ।		35–40
माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड का उद्घाटन भाषण (अनुबन्ध 'क')		41
माननीय मुख्य मन्त्री का उद्घाटन भाषण (अनुबन्ध 'ख')		42–44
दो दिवसीय बैठ्कों की जिलावार समय सारणी।		45
जिलावार / चुनाव क्षेत्रवार बैठ्कों में भाग लेने वाले माननीय मन्त्रियों एवं विधायकों का ब्यौरा ।		46–47

वार्षिक योजना 2026–27 की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए माननीय विधायकों के साथ दिनांक 06 तथा 07 फरवरी, 2026 को श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु, माननीय मुख्य मन्त्री, की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठकों की कार्यवाही ।

....

सर्वप्रथम श्री देवेश कुमार, प्रधान सचिव (योजना) ने माननीय मुख्य मन्त्री, समस्त माननीय मन्त्रीगण, उपाध्यक्ष (राज्य योजना बोर्ड), उप–मुख्य सचेतक(हि0प्र0वि0स0), माननीय विधायकों, मुख्य सचिव, समस्त प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं अन्य उपस्थित अधिकारियों का वार्षिक बजट 2026–27 के लिए माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठकों में स्वागत किया।

उन्होंने इन बैठकों में यह उल्लेख किया कि राज्य के आगामी वार्षिक बजट 2026–27 की रूपरेखा तैयार करने तथा माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को इसमें सम्मिलित करने हेतु इन महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन करते रहे हैं। उन्होंने माननीय मुख्य मन्त्री का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के उपरान्त भी इन बैठकों के लिए दो दिन का बहुमूल्य समय प्रदान किया। प्रधान सचिव (योजना) ने कहा कि माननीय विधायकों के साथ यह विचार–विमर्श अत्यंत सार्थक सिद्ध होता है। इन बैठकों के माध्यम से न केवल माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों की प्राथमिकताओं को उपलब्ध करवाते हैं बल्कि कई अति महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि मितव्ययता, वित्तीय संसाधन जुटाना, प्रशासनिक सुधार एवं बेहतर प्रशासन, स्वरोजगार व wage employment सृजित करने के लिए भी बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होते हैं। यह सभी सुझाव राज्य के आगामी वार्षिक बजट तैयार करने तथा प्रदेश के सन्तुलित सर्वांगीण, सत्त एवं हरित विकास के लिए कारगर सिद्ध होते हैं।

प्रधान सचिव (योजना) ने स्पष्ट किया है कि सम्बन्धित विभाग, विधायक प्राथमिकताओं की योजनाओं की प्रगति की जानकारी समय–समय पर विधायकों को उपलब्ध करवाते हैं तथा उनसे यह आशा है कि भविष्य में भी इन सूचनाओं का आदान–प्रदान सुचारू रूप से चलता रहे। माननीय विधायकों के क्षेत्रीय अनुभवों का लाभ स्थानीय स्तर की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिये लिया जा सकता है, जिससे विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को गति मिल सके। प्रधान सचिव (योजना) ने यह भी बताया कि माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं की योजनाओं को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव के स्तर पर भी योजनाओं की समीक्षा की जाती है। उन्होंने समस्त प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि वह अपने स्तर पर नियमित रूप से विधायक प्राथमिकताओं की समीक्षा करें। और कार्यों को गति प्रदान करें। साथ ही यह भी आग्रह किया कि सभी विभाग माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से माननीय विधायकों के साथ योजना विभाग को भी सूचित करेंगे।

प्रधान सचिव (योजना) ने सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों की ओर से आश्वासन दिया कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने इस बात से भी सभी माननीय विधायकों को अवगत करवाया कि वर्ष 2014–15 से 2020–21 तक की ट्रांचिज़ (Tranches) नाबार्ड द्वारा बन्द की जा चुकी हैं। अतः इस अवधि की सभी विधायक प्राथमिकताएं जिनकी डी.पी.आर. नहीं बनी है समाप्त कर दी गई हैं। तत्पश्चात प्रधान सचिव(योजना) ने उपाध्यक्ष (राज्य योजना बोर्ड) तथा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से सभी उपस्थित माननीय विधायकगण व सभी सचिवों तथा विभागाध्यक्षों का मार्गदर्शन करने हेतु आग्रह किया ।

माननीय उपाध्यक्ष (राज्य योजना बोर्ड) का स्वागत भाषण **(अनुबन्ध–"क")** पूर्ण होने के बाद माननीय मुख्य मंत्री ने अपने उदघाटन भाषण **(अनुबन्ध–"ख")** से सभी का अभिवादन और मार्गदर्शन किया। इसके उपरान्त चुनाव क्षेत्रवार बैठकों का शुभारम्भ किया गया। जिला एवं चुनाव क्षेत्रवार दो दिवसीय बैठकों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	जिला / माननीय विधायक / निर्वाचन क्षेत्र / बैठकों में उठाये गए मुद्दे	सम्बन्धित विभाग
1.	2.	3.
	1. जिला ऊना	
	1. श्री सुदर्शन सिंह बबलु, चिन्तपूर्णी	
1.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
2.	उठाऊ पेयजल योजना स्थोतर, धन्दयाड़ी, कुठ्याड़ी की डी.पी.आर. तैयार है। इसे स्वीकृत करवाया जाए।	जल शक्ति विभाग
3.	जल शक्ति विभाग में तकनीकी तथा गैर–तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी है, इससे कार्ययोजना तैयार करने में दिक्कत आ रही है। अतः 150 पैरा वर्कर पद स्वीकृत व भर्ती करने की कृपा करें ताकि काम सुचारू रूप से चल सके।	जल शक्ति विभाग

4.	स्थोतर पुल का काम SCDP Component के तहत किया जा रहा है जो पूरा नहीं हुआ है। इस Component के तहत fund प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः पुल के कार्य को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण / ESOMA विभाग
5.	चौकी–मनियार कॉलेज भवन के अधूरे कार्य को पूरा करवाया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
6.	रा0व0मा0पा0 अम्ब में साईंस व कॉमर्स ब्लॉक का काम अधूरा पड़ा है, इसके लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान कर कार्य को पूरा किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
7.	अम्ब फायर स्टेशन को अपग्रेड किया जाए व एक फायर सब–स्टेशन जोल में खोला जाए।	अग्निशमन विभाग
8.	सिद्धचलेट से खलपाती सड़क का कार्य SCDP Component के तहत किया जा रहा है, अभी तक केवल 60 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ है, शेष कार्य के लिए धन का प्रावधान कर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण / ESOMA विभाग
9.	चिन्तपूर्णी से अमलेहड़ सड़क जो अस्पताल को भी जोड़ती है की दयनीय स्थिति को सुधारा जाए, जिसके लिए उचित धन का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
10.	माता का बाग योजना के तहत लगभग 4 करोड़ रू0 की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, परन्तु इस पैसे को जारी करने पर रोक लगी है। आपसे अनुरोध है कि मन्दिर परिसर में पानी एवं अन्य व्यवस्थाओं का सुचारू संचलान सुनिश्चित करने के लिए इस रोक को हटाकर धनराशि जारी की जाए।	भाषा कला एवं संस्कृति / जल शक्ति विभाग
11.	लोहारली में लगभग 50 करोड़ रू0 की लागत से पुल बनकर तैयार है लेकिन जमीनी विवाद के चलते अप्रोचिज़ का कार्य लम्बित है क्योंकि कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। इस स्टे को हटवाकर कार्य को पूर्ण किया जाए, ताकि स्थानीय जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके।	लोक निर्माण विभाग
12.	माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं मिनी सचिवालय तथा ईन्डोर स्टेडियम के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए धन की उचित व्यवस्था की जाए।	राजस्व / युवा खेल सेवाएं विभाग
13.	चिन्तपूर्णी मन्दिर के विस्तारीकरण व प्रसाद वितरण के लिए राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से लगभग 130 करोड़ रू0 प्राप्त हुए हैं। इस कार्य को शीघ्र आरम्भ किया जाए।	भाषा कला एवं संस्कृति विभाग
	2. श्री राकेश कालिया, गगरेट	
1.	गगरेट अस्पताल का काम पूरा करने के लिए 1.26 करोड़ की राशि का प्रावधान कर कार्य को पूरा किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
2.	यदि किसी भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है तो उस भवन का उदघाटन कर उसे सम्बन्धित विभाग को सौंप दिया जाए ताकि भवन उपयोग में लाया जा सके और यदि कोई liability शेष है तो उसे विभाग बाद में चुकता कर दे।	समस्त सम्बन्धित विभाग
3.	लोगों द्वारा Fecal Sludge को टैंकरस के द्वारा नदी नालों में बहाया जा रहा है। इसे रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांटस लगाने की आवश्यकता है, ताकि लोग उस Fecal Sludge को ट्रीटमेंट प्लांटस में ही डाल सकें।	शहरी विकास/ जल शक्ति विभाग
4.	रा0व0मा0पा0 रामनगर, घनारी, नगड़ोह, मरवाड़ी और प्रशासनिक भवन ओयल इत्यादि 6 ऐसे भवन हैं जिनका 80–90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य को पूर्ण कर इन भवनों को चालू किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
5.	रा0व0मा0पा0 अंबोटा में स्टेडियम निर्माण हेतु 25 लाख रू0 स्वीकृत किये गए थे। इसके निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कर इसे चालू किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
6.	राजीव गाँधी डे बोर्डिंग स्कूल के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण करने के लिए धनराशि की उचित व्यवस्था की जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
7.	निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की तारों और खम्बे इत्यादि स्थानांतरित करने के लिए या बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए बजट का अलग से प्रावधान किया जाए।	HPSEBLtd.
8.	दौलतपुर तथा मुबारिकपुर सीवरेज योजना के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
9.	पी.एच.सी. अमलेहड़ को अपग्रेड किया जाए और एक महिला विशेषज्ञ चिकित्सक के पद को भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग

	3. श्री सतपाल सिंह सत्ती, ऊना	
1.	विधायक प्राथमिकताओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी योजना विभाग द्वारा इन बैठकों में ही उपलब्ध करवाई जाती है। इस जानकारी को प्रत्येक तीन महीने में विधायकों को उपलब्ध करवाने बारे विभाग उचित कार्रवाई करे।	योजना विभाग
2.	नगर निगम ऊना में 14 गाँवों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ सीवरेज तथा पानी की समस्या है। पानी की समस्या को हल करने के लिए भभौर साहिब से पानी उठाने की योजना बनाई जाए।	जल शक्ति विभाग
3.	ऊना में पिछले दो वर्षों में भारी बरसात के कारण भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पुराने उपायुक्त कार्यालय व लोगों के घरों में पानी भर जाता है। इसे रोकने के लिए जगह–2 पर 8 बड़े ड्रेनेज और आवश्यकतानुसार कुछ छोटे–2 ड्रेनेज बनाने के लिए विधायक प्राथमिकता योजनाओं के तहत पैसा दिया जाए।	जल शक्ति विभाग
4.	भभौर साहिब से ऊना पानी की स्कीम की remodeling & strengthening के लिए 132 करोड़ रू0 की डी.पी.आर. केन्द्र सरकार में CWC को funding हेतु गई है। यह स्कीम लगभग 2600 है0 क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। अतः CWC के समक्ष मुददा उठाया जाए ताकि स्कीम को fund प्राप्त हो सकें।	जल शक्ति विभाग
5.	ऊना विधान सभा क्षेत्र के संतोषगढ़ से लगते 8 गाँवों सनोली, मिहारा, छत्रपुरढाडा, अजोली, इत्यादि में बरसात के समय जलभराव हो जाता है, जिससे 15000 लोगों की आबादी को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, इस समस्या को दुरूस्त करने के लिए water storage योजना की डी.पी.आर. बनाई जाए व इसे स्वीकृत करवाया जाए ताकि समस्या का निदान हो सके	जल शक्ति विभाग
6.	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना तथा विधायक ऐच्छिक निधि के तहत धनराशि जारी नहीं हो रही है, इन्हें जारी किया जाए।	योजना / ग्रामीण विकास विभाग
7.	मिनी सचिवालय ऊना के द्वितीय चरण की डी.पी.आर. बनाई जाए, ताकि पुराने उपायुक्त कार्यालय में चल रहे विभागों और उपभोक्ता अदालत कार्यालय को इसमें संचालित किया जा सके।	राजस्व विभाग
8.	पिछली भारी बरसात में रामपुर पुल गिर गया था वहाँ पर वैली ब्रिज का निर्माण किया गया है जिसकी भार उठाने की क्षमता लगभग 18 टन ही है। लेकिन यहाँ से 50–60 टन क्षमता वाले बड़े वाहन गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी पुल टूटने का खतरा है। अतः इस पुल की 16 करोड़ रू0 की डी.पी.आर. जो सरकार को बनाकर भेजी गई है को शीघ्र स्वीकृत किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
9.	बी.डी.ओ. कार्यालय ऊना का कार्य पूरा करने के लिए केवल 1.25 करोड़ रू0 की आवश्यकता है। इस राशि का प्रावधान कर निर्माण कार्य पूरा किया जाए और भवन को सम्बन्धित विभाग को सौंपा जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
10.	पी.जी.आई. Satellite Centre ऊना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए राज्य सरकार से 3 करोड़ रू0 की धनराशि अपेक्षित है। इस राशि को जारी किया जाए ताकि निर्माण कार्य पूरा हो सके।	जल शक्ति विभाग
	4. श्री विवेक शर्मा, कुटलैहड़	
1.	गोविन्द सागर झील से ग्राम पंचायत लठ्याणी, बुधान के लिए 29 करोड़ रू0 की लागत की डी.पी.आर. को विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत शीघ्र स्वीकृत किया जाए।	जल शक्ति/ योजना विभाग
2.	सीवरेज स्कीम बंगाणा के शेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए 6 करोड़ रू0 की शेष धनराशि को शीघ्र जारी किया जाए ताकि निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो सके।	जल शक्ति विभाग
3.	कुटलैहड़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की गोविन्द सागर–भरमाती हंडोला सिंचाई योजना की डी.पी.आर. रू0 46.37 करोड़ की PMKSY के तहत भारत सरकार को भेजी गई है, इसे शीघ्र स्वीकृत करवाया जाए।	जल शक्ति विभाग
4.	बसाल क्षेत्र में 10 नए ट्यूबवैलों की स्थापना की जाए।	जल शक्ति विभाग

5.	माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा, धनेत पुल जो हैलीपोड के साथ बनना है, की डी.पी.आर. शीघ्र बनाकर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
6.	बंगाणा–शांतला–तुतडु–कांगड़ा सड़क repair, maintenance and drainage की डी. पी.आर. भारत सरकार को भेजी गई है इसे CRIF के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करवाई जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	लठ्याणी–कोहडरा सड़क तथा पर्यटन की दृष्टि से थानाकलां–भाखड़ा सड़क की डी.पी.आरज़ जो कि सरकार के पास विचाराधीन हैं को शीघ्र स्वीकृत किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8.	लठ्याणी पी.एच.सी. को अपग्रेड किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
9.	बंगाणा बस स्टैण्ड एफ.सी.ए. मामले को वन विभाग द्वारा शीघ्र स्वीकृति प्रदान करवाई जाए।	वन विभाग/ बस अडडा प्राधिकरण
10.	मनोहर मार्केट से धमान्दरी सड़क का निर्माण/सुदृढ़ीकरण करवाया जाये।	लोक निर्माण विभाग
11.	बीहडू में पुलिस चौकी खोली जाए।	पुलिस विभाग
12.	बंगाणा में सब जज कोर्ट खोला जाए।	राजस्व विभाग
13.	मसैणी खडड का तटीयकरण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
14.	रायपुर तथा बल्ह में पटवार सर्कल खोले जाएं।	राजस्व विभाग
15.	रा0व0मा0पा0 बंगाणा तथा पिपलू में साईंस ब्लॉक के शेष 10 प्रतिशत निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
16.	तहसील कार्यालय भवन बनकर तैयार है। इसकी लगभग 1 करोड़ रू0 की देनदारी शेष है, इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/राजस्व विभाग
	2. जिला हमीरपुर	
	1. श्री सुरेश कुमार, भोरंज	
1.	निर्वाचन क्षेत्र भोरंज के लदरौर–पटटा के लिए गोविन्द सागर से बनने वाली पेयजल योजना की डी.पी.आर. केन्द्रीय शीर्ष में किन्हीं नियमों / कारणों से स्वीकृत नहीं हो पाई है। राज्य सरकार इसे अपने किसी राज्य शीर्ष से शीघ्र स्वीकृत करवाकर इसका निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	जल शक्ति विभाग
2.	मेवा–बमसन पेयजल योजना को बने लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। इसकी पुरानी मशीनरी तथा राईजिंग मेन को नई मशीनरी को बदलने तथा मुरम्मत के लिए धन का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
3.	क्षेत्र में low voltage की समस्या है जिस कारण व्यास नदी पर बनी सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन में बाधा आती है इसलिए जाहू क्षेत्र में 33 के.वी. ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया जाए ताकि जितनी भी पानी की स्कीमें हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाया जा सके।	HPSEBLtd./ जल शक्ति विभाग
4.	नई बनी भोरंज नगर पंचायत के पास न तो कोई infrastructure बना है न ही स्टॉफ है। इसके लिए बजट प्रदान कर इस समस्या का समाधान किया जाए।	शहरी विकास/ नगर एवं ग्राम योजना विभाग
5.	जल शक्ति सब–डिवीजन कंजयाण के लिए अपने स्थायी भवन का निर्माण पूरा करने के लिए 2.50 करोड़ रू0 की आवश्यकता है, इसका प्रबन्ध किया जाए।	जल शक्ति विभाग
6.	जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह जाहू (2.25 crore liability) तथा अम्मण का 80–90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य के लिए उचित धन की व्यवस्था कर निर्माण कार्य को पूर्ण कर इसे चालू किया जाए।	जल शक्ति विभाग
7.	भोरंज सब–जज कोर्ट भवन निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	राजस्व विभाग
8.	भोरंज में सीवरेज प्रणाली के लिए funds दिए जाएं।	जल शक्ति विभाग
9.	रा0व0मा0पा0 समीरपुर में साईंस बलॉक का निर्माण किया जाए। इस स्कूल की जमा दो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 300+ है।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
10.	भोरंज अस्पताल में चिकित्सकों के आवासीय परिसर का निर्माण किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
11.	वैटनरी अस्पताल जाहू के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए लगभग 35–40 लाख रू0 की राशि जारी कर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।	पशु पालन विभाग

	2. कैप्टन रंजीत सिंह राणा, सुजानपुर	
1.	पिछले वर्ष हुई भारी बरसात में जोल पलाही, बीड़ बघेड़ा, जंगल, खैरी, खनोली, इत्यादि जगहों पर भारी नुकसान हुआ था तथा माननीय मुख्यमंत्री ने जगह-जगह डंगे लगाने के निर्देश दिये थे, पर इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बारे कार्रवाई अमल में लाई जाए।	लोक निर्माण/ राजस्व / ग्रामीण विकास/ पंचायती राज विभाग
2.	जल शक्ति विभाग की Inspection Hut बनाने के लिए funds प्रदान कर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
3.	हमीरपुर-पालमपुर सड़क पर सुजानपुर के पास लगभग 15 मीटर का तंग पुल है इसके स्थान पर बड़े पुल का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	सुजानपुर-संधोल सड़क का निर्माण कार्य / वाईडनिंग कार्य चला है, यहॉँ पर भी 6-7 मीटर का तंग पुल है इसके स्थान पर भी डबल लेन पुल का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
5.	जल शक्ति विभाग के अधीन सुजानपुर में 28-30 योजनाओं की पुरानी मशीनरी को बदला जाए। साथ ही इन योजनाओं के लिए बड़ी हैवी मशीनरी/उपकरणों का उपयोग किया जाए।	जल शक्ति विभाग
6.	जल शक्ति विभाग में JJM के तहत बन रहे रैस्ट हाउस भवन निर्माण कार्य को बजट उपलब्ध करवाकर तीव्रगति से पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
7.	पी.एच.सी. चबूतरा के भवन निर्माण का कार्य लगभग 80-90 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है, शेष कार्य को पूरा करने के लिए उचित धनराशि का प्रावधान कर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
8.	बी.डी.ओ. कार्यालय सुजानपुर के निर्माण के लिए अगली किश्त जारी की जाए तथा कार्य को तय अवधि में पूरा किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
9.	टौणीदेवी-उहल-कक्कड़-चूही-जंगलबेरी सड़क को चौड़ा करने के लिए धन का प्रावधान कर इसका कार्य जल्द आरम्भ / पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
10.	33 के.वी. ट्रांसफॉर्मर जंगलबैरी में लगाया जाए इसके साथ-साथ J.E. कार्यालय भवन में सहायक अभियन्ता को तैनात किया जाए/ बैठाया जाए।	HPSEBLtd.
11.	अनसेफ हाई स्कूल पटनौण के भवन निर्माण के लिए 10 लाख रू0 की धनराशि जारी की गई है, रू0 7 लाख की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान कर निर्माण कार्य पूरा किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
12.	रा0व0मा0 पा0 कक्कड़ के अनसेफ भवन के स्थान पर जब तक नए भवन का निर्माण कार्य पूरा न हो तब तक 3-4 कमरों के निर्माण हेतु लगभग 25-30 लाख रू0 की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान कर निर्माण कार्य पूरा किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
13.	कृषि विभाग के तहत फसलों को बेसहारा / जंगली जानवरों से बचाने के लिए लगाई जाने वाली तारों की ऊंचाई 6-8 फीट की जाए और यदि किसी व्यक्ति का कार्य पुराने नियमों (लगभग 4 फीट) में हो रहा है तो इसे भी नए नियमों(लगभग 6-8 फीट) के तहत पूरा किया जाए।	कृषि विभाग
14.	टौणी देवी अस्पताल में आर्थो का तथा सुजानपुर अस्पताल में मेडिसीन के चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए। इसके साथ-साथ सुजानपुर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन अतिशीघ्र लगाई जाए।	स्वास्थ्य विभाग
15.	कक्कड-धर्मपुर बस को वाया दियाणा, धर्मपुर, गददीधार आगे चलाया जाए।	HRTC
	3. श्री ईन्द्र दत्त लखनपाल, बड़सर	
1.	बस अडडा मैहरे/बड़सर तथा भोटा के निर्माण कार्य को शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
2.	24x7 पीएचसी भोटा, डॉक्टरों व स्टाफ नर्सों की कमी के कारण केवल दिन में ही चलती है। अतः डॉक्टरों व स्टाफ नर्सों की उचित व्यवस्था कर इसे 24x7 चलाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
3.	माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सिविल अस्पताल बड़सर को 100 बिस्तर करने बारे विभाग शीघ्र कार्रवाई करे।	स्वास्थ्य विभाग
4.	सिविल अस्पताल बड़सर में 50 बिस्तर Critical Care Unit खोलने की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना का कार्य आरम्भ किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग

5.	क्षेत्र की तीन आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरीज / अस्पतालों चम्बोह, टिक्कर राजपूतां तथा दलचेहड़ा में फार्मासिस्ट तथा डॉक्टरों के पद स्वीकृत कर इन्हें चालू किया जाए।	आयुर्वेदा विभाग
6.	आयुर्वैदिक हैल्थ सेन्टर कुलेहड़ा को डिनोटिफाई किया गया था इसे पुनः बहाल किया जाए।	आयुर्वेदा विभाग
7.	अस्थाई पुलिस चौकी बिझड़ी तथा भोटा को अपग्रेड/स्थायी किया जाए।	पुलिस विभाग
8.	निर्वाचन क्षेत्र में आधे से डेढ ईंच की पाईपों की कमी को दूर किया जाए।	जल शक्ति विभाग
9.	बड़सर में रू0 132 करोड़ की लागत से बनने वाली सिंचाई / पेयजल योजना के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए साथ ही इस योजना निर्माण लाभ से छूटे क्षेत्र जैसे दैण, ठठियार, कन्नड़ तथा बलरतनू को भी इसमें शामिल कर इनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
10.	SCDP कम्पोनेंट के तहत सड़कों को पैसा नहीं आ रहा है जिससे इन सभी का काम रूका पड़ा है। अतः इन सड़कों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु बजट का पूर्ण प्रावधान किया जाए जैसेः समताना–संगेड़ी सड़क, बड़ाग्रां–गुरुबन सड़क, बड़सर–सत्रुकाह सड़क, लिंक रोड़ भटलाड़–भालत, लिंक रोड़ कुरियाह से भलत, लिंक रोड़ गॉंव सेर–हरदोह, लिंक रोड़ टिल्लू–अम्बीड़ी इत्यादि।	लोक निर्माण विभाग / ESOMA Deptt.
11.	रैली जजरी के स्कूल के जर्जर भवन को गिराकर नए भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
12.	पंजैहड़ा सोलर प्लांट के लिए 12 बीघा भूमि का चयन भी कर लिया गया है शीघ्र इस योजना का निर्माण किया जाए।	हिम ऊर्जा
13.	पी.एच.सी. भवन चकमोह बनकर तैयार है इसका उदघाटन कर इसे चालू किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
14.	बिझड़ी अग्निशमन केन्द्र का भवन बनकर तैयार है इसे चालू किया जाए।	अग्निशमन विभाग
15.	क्षेत्र के निर्माणाधीन मुख्यमंत्री लोक भवन के लिए धनराशि जारी कर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
16.	दियोटसिद्ध से दिल्ली के लिए एक वॉल्वो बस चलाई जाए। इसके साथ–साथ बड़सर से एम्स बिलासपुर के लिए विशेष बस चलाई जाए।	HRTC
17.	मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में डायलिसीज के लिए लम्बी डेटस मिलती हैं। इस बारे सरकार कोई ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार करे कि यह डायलिसीज कम समय पर की हो जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
18.	बी.बी.एन. ट्रस्ट में रिक्त चल रहे पदों को सरकार भरे तथा इस ट्रस्ट के कॉलेज का सरकार अधिग्रहण कर इसमें नये विषयों का संचालन किया जाए और भवन निर्माण भी किया जाए जिसके लिए स्थानीय लोगों ने भूमि भी दान कर दी है।	भाषा कलां एवं संस्कृति / शिक्षा विभाग (उच्चतर/स्कूल)
19.	मैहरे तथा बड़सर को नगर पंचायत बनाया गया है इसमें पड़ने वाले कृषि वाले क्षेत्र बणी, ठाणा, रैल, मकतेड़ी, तुखाणी इत्यादि को नगर पंचायत से बाहर किया जाए।	शहरी विकास विभाग
20.	भारी बरसात से क्षेत्र की सड़कों को भारी नुकसान हुआ है तथा AMP का पैसा भी कम आया है। इनके लिए बजट का प्रावधान किया जाए ताकि इन सड़कों की मुरम्मत व रख–रखाव कार्य सम्पन्न हो सकें।	लोक निर्माण विभाग
21.	वन विभाग की इन्स्पैक्शन हट धबड़ियाना, वन विश्राम गृह समैला तथा बड़सर में चौकीदारों की नियुक्ति की जाए तथा इनका उचित रख–रखाव व सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए।	वन विभाग
	3. जिला सिरमौर	
	1. श्रीमति रीना कश्यम, पच्छाद	
1.	सराहन से चण्डीगढ़ सड़क की दयनीय स्थिति को गुणवत्ता के साथ सुधारा जाए।	लोक निर्माण विभाग
2.	सरकारी बस रूट सराहां–मिंदोबाग–नाबल खोजर को बन्द न किया जाए।	HRTC
3.	सराहां अस्पताल को 100 बिस्तर करने की रदद की गई अधिसूचना को पुनः बहाल कर चिकित्सकों के रिक्त पदों को भी भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग

4.	राजगढ़ अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाए साथ ही अल्ट्रासाउंड की मशीन के सुचारू संचालन हेतु रेडियोलॉजिस्ट के पद को भी भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	क्षेत्र की हाब्बन वैली, शिरगुल महोदव की जन्म स्थली शाया मन्दिर, भुरेश्वर महादेव इत्यादि क्षेत्र में विद्यमान मन्दिरों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन/ भाषा कला एवं संस्कृति विभाग
6.	जल शक्ति विश्राम गृह राजगढ़ के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए लगभग 50–60 लाख रू0 की धनराशि उपलब्ध करवाकर कार्य पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
7.	क्षेत्र की सिंचाई / पेयजल योजनाओं की पुरानी पम्पिंग मशीनरी को बदलने की विधायक प्राथमिकता की डी.पी.आर. को शीघ्र स्वीकृत कर कार्य को अविलम्ब आरम्भ / पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	5–6 पंचायतों को जोड़ने वाला पधेली पुल भारी बरसात के कारण बह गया था, के निर्माण कार्य के लिए धनराशि जारी कर इसका कार्य शीघ्र आरम्भ / पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
9.	रा0व0मा0 पाठशाला हाब्बन के अधूरे भवन निर्माण कार्य को पूरा किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
10.	विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी की जाए।	योजना विभाग
	2. श्री अजय सोलंकी, नाहन	
1.	मेडिकल कॉलेज नाहन के लम्बित कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए तथा कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट के पद सृजित किए जाएं तथा स्टाफ नर्सिज़ के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
2.	भोगपुर–सिंबलवाला गॉँव सड़क पर 6.58 करोड़ रू0 लागत से बनने वाले पुल का निर्माण अतिशीघ्र किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
4.	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP) तथा MNP के तहत चालू योजनाओं में पूर्ण बजट का प्रावधान कर इनका निर्माण कार्य पूरा किया जाए।	ESOMA Deptt./ लोक निर्माण विभाग
5.	धारटीधार क्षेत्र के लिए बनाई गई सिंचाई योजना की डी0पी0आर0 को शीघ्र स्वीकृत कर कार्य अविलम्ब पूरा किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।	जल शक्ति विभाग
6.	मेडिकल कॉलेज नाहन के निर्माण के लिए जल शक्ति विभाग के आवासीय भवनों को तोड़ा गया था, इनके स्थान पर नई आवासीय कलौनी का निर्माण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाए।	स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा विभाग
7.	जल शक्ति विभाग के सब–डिवीजन कार्यालय पावंटा साहिब के अधीन क्षेत्र की पांच पंचायतों के लिए बनने वाली माजरा–मिसरवाला–मेलू–जगतपुर–कयारधा सीवरेज स्कीम की डी.पी.आर. को 'नमामि गंगे योजना' से स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य आरम्भ / पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 50 ट्यूबवैल की डी.पी.आर. को शीघ्र स्वीकृत किया जाए।	जल शक्ति विभाग
9.	निर्वाचन क्षेत्र में चल रही लो–वोल्टेज की समस्या को हल किया जाए तथा दूर–दराज के क्षेत्रों में ट्रॉंसफॉर्मर लगाने के कार्य को तीव्रगति से अविलम्ब पूरा किया जाए। इसके साथ–साथ World Bank की सहायता से नाहन तथा पावंटा टाउन में चल रहे बिजली के कार्यो (Transformer installation & upgradation, underground cabling, etc.)को भी जल्द पूरा किया जाए।	HPSEBLtd./ HPPTCLtd.
10.	नाहन–नैरसवार रूट पर चलने वाली सरकारी बस को बन्द किया गया है इसे चालू किया जाए।	HRTC
11.	आदर्श स्वास्थ्य संस्थान धगेड़ा में एक्सरे मशीन को चालू किया जाए तथा चिकित्सकों व रेडियोग्राफर के रिक्त पदों को भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
12.	बी.एम.ओ. धेगड़ा नाहन में बैठते हैं इन्हें धगेड़ा में ही बैठाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग

	3. श्री विनय कुमार, श्री रेणुका जी	
1.	धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से लगभग 100 कि0मी0 लम्बी सोलन–मीनस सड़क की डी.पी.आर. को CRIF के तहत स्वीकृत करवाकर इसका सुदृढ़ीकरण / सुधारीकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2.	दोसड़का–रेणुका जी सड़क का अपग्रेडेशन किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	रेणुका डैम प्रोजेक्ट के बनने से मुख्य सड़क संगड़ाह को बन्द कर किसी अन्य स्थान से बनाया जाना है जिससे 14 कि0मी0 की दूरी बढ़ रही है। इस सड़क के स्थान पर यहां पर एक सुरंग (1.5 से 2 कि0मी0) का निर्माण किया जाए।	HPPCLtd. / लोक निर्माण विभाग
4.	आदर्श स्वास्थ्य संस्थान संगड़ाह में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए, एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाई जाए तथा चिकित्सक जिन्हें स्थानांतरित किया गया है उन्हें वापिस किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	संगड़ाह में बी.एम.ओ. अपनी डयूटी पर नहीं आता इस बारे विभाग उचित कार्रवाई करे।	स्वास्थ्य विभाग
6.	क्षेत्र के जितने भी अस्पताल हैं उनमें डैड हाउस अनिवार्य किया जाए ताकि मृतक का वहीं पर पोस्ट मार्टम किया जा सके, विशेषकर नौहराधार तथा हरिपुरधार।	स्वास्थ्य विभाग
7.	राजकीय महाविद्यालय ददाहू, बस स्टैण्ड ददाहू तथा ददाहू ब्लॉक के लिए एफ.सी.ए. शीघ्र स्वीकृत की जाए।	बस अडडा प्राधिकरण वन/शिक्षा(उच्चतर) / ग्रामीण विकास विभाग
8.	नौहराधार में बस स्टैण्ड बनाने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। इसके लिए भूमि भी हस्तांतरित की जा चुकी है।	बस अडडा प्राधिकरण
9.	संगड़ाह में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु स्थानीय लोग अपनी भूमि दान कर रहे हैं लेकिन विभाग के कर्मचारी/ अधिकारी मौके पर ही नहीं आ रहे हैं इस बारे विभाग उचित कार्रवाई करे।	परिवहन विभाग/ बस अडडा प्राधिकरण
10.	संगड़ाह में विद्युत विभाग का सब–डिवीजन खोला जाए।	HPSEBLtd.
11.	क्षेत्र में सब–जज कोर्ट खोला जाए।	राजस्व विभाग
12.	रेणुका झील में बढ़ रही सिल्ट को निकालने बारे (desilting) विभाग उचित कार्रवाई करे। प्रदेश सरकार चाहे अपने स्तर पर या भारत सरकार के स्तर पर इस मुददे को हल करे।	Env. Sci. Tech. Deptt.
13.	Wild Life Sanctuary रेणुका जी में Tiger pair को अतिशीघ्र लाया जाए।	वन विभाग(Wild life wing)
14.	संगड़ाह में फॉयर स्टेशन खोला जाए।	अग्निशमन विभाग
15.	विद्युत विभाग में बिजली के चल रहे Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के कार्य को पहले ग्रामीण क्षेत्रों से आरम्भ किया जाए।	HPSEBLtd.
16.	सी.एच.सी. नौहराधार के कार्य को पूर्ण किया जाए तथा पी.एच.सी. चौकर के कार्य को पूरा करने के लिए धन का प्रावधान किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
17.	क्षेत्र में विद्यमान स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
18.	निर्वाचन क्षेत्र के जिन Single Teacher स्कूलों में से शिक्षकों को स्थानांतरित किया गया है उन्हें वापिस लाया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
19.	बेचड़बाग साईंस लैब निर्माण कार्य को बजट उपलब्ध करवाकर पूर्ण किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
20.	बरसात में बह गए 2–3 स्कूलों में कमरों के निर्माण हेतु बजट उपलब्ध करवाकर कमरों का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
21.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को 25–30 करोड़ रू0 बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
	4. श्री सुखराम चौधरी, पावंटा साहिब	
1.	रा0व0मा0पा0 नगेता, सांईस लैब रा0व0मा0पा0 पुरूवाला तथा राजकीय महाविद्यालय गुरू गोविन्द सिंह के कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं, शेष कार्य पूर्ण करने के लिए बजट जारी किया जाए और निर्माण कार्यो को पूरा किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
2.	सी.एच.सी. राजपुरा के निर्माण कार्य को पूरा करने लिए धन का प्रावधान किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग

3.	नावघाट–विकासनगर–सिंगपुरा–भगाणी यमुनानगर पुल जो हिमाचल को उतराखण्ड से जोड़ता है के लिए हिमाचल की तरफ से भूमि का अधिग्रहण कर सड़क का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	MDR बांगरण–पुरुवाला–सिंगपुरा सड़क (लगभग 26.5 कि0मी0) पावंटा को उतराखण्ड से जोड़ती है की दयनीय स्थिति को सुधारा जाए/ सुदृढ़ीकरण किया जाए। इसके साथ–साथ इस सड़क पर बांगरण के पास सिंगल लेन पुल बना है यहां पर डबल लेन पुल (लगभग 48.71 करोड़) बनना है। इस पुल तथा सड़क की डी.पी.आर. को CRIF में प्रस्तावित कर स्वीकृत करवाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
5.	देवीनगर–रामपुरघाट–नवादा 7 कि0मी0 लम्बी सड़क की दयनीय स्थिति को ठीक किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
6.	लगभग 30 कि0मी0 लम्बी सड़क पुरुवाला–नगेता–कलाथा बधाणा–किलोड़ को MDR घोषित किया जाए तथा इसकी मैटलिंग टारिंग / सुदृढ़ीकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	पिछली बरसात में फूलभर पंचायत में, बांगरण में बहुत नुकसान हुआ है यहां एक जल शक्ति विभाग की स्कीम पूरी बह गई जो लगभग 1000 बीघा भूमि को सिंचित करती थी, एक सड़क बह गई है। इसलिए विशेष रूप से इस क्षेत्र बांगरण में गिरी नदी का तटीयकरण करने के लिए बजट का अलग से प्रावधान कर channelization का कार्य अविलम्ब आरम्भ कर पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	गिरी दायां तट तथा बायां तट नहरों की मुरम्मत PMKSY में या अन्य किसी माध्यम से की जाए।	जल शक्ति विभाग
9.	खेतों में सिंचाई के लिए 7 ईंच के लगभग 150 ट्यूबवैल लगाए गये हैं लेकिन मोटर नहीं लगाई गई हैं। इस विषय में किसानों को मोटर लगाने के लिए अधिकृत (authorize) किया जाए या सरकार जल्द इन ट्यूबवैलों में मोटरें लगाए।	जल शक्ति विभाग
10.	220 सब–स्टेशन राजबन में शीघ्र लगाया जाए।	HPSEBLtd./ HPPTCLtd.
	4. जिला सोलन	
	1. श्री संजय अवस्थी, अर्की	
1.	पिछली भारी बरसात में सड़कों को काफी नुकसान हुआ है, विशेषकर जैसे कि जाबल से मनलोग कलां, उख्खु, जयनगर, लोहारधार सड़क की दयनीय स्थिति को ठीक किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2.	पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं को भी भारी नुकसान हुआ है इन्हें भी ठीक करने के लिए उचित बजट का प्रावधान किया जाए। जैसे कि Augmentaton of LWSS चड़ी चौरट्टू, गम्भर खडड से बनने वाली LIS भूमतिधार ब्राहम्णा सिंचाई योजना, Remodeling, renovation and extension of various Lift Irrigation Schemes in Arki constituency, Providing LWSS to village बरसणु, फगवसना समाना और सेरा in GP कोटलू in Arki constituency, Remodeling of LWSS Newdi.	जल शक्ति विभाग
3.	क्षेत्र की निम्नलिखित सड़कों के लिए बजट की उचित व्यवस्था की जाए जैसे कि अपग्रेडेशन ऑफ बथालंग–जाबड़ा–पलोग राऊ सड़क, अपग्रेडेशन ऑफ जाबल–बड़ाल–नाशु नाला सड़क, बियाली से कल्याणघाटी सड़क, धार का डोरा–बाणहाटलू सड़क इत्यादि।	लोक निर्माण विभाग
4.	मांगल पंचायत से मलोखर तक सुरंग के निर्माण कार्य तीव्रगति से पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
5.	बैरल क्षेत्र से आगे कोलडैम के साथ सुन्दरनगर को जोड़ने वाले पैदल पथ /पुल का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
6.	बाड़ीधार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए रोपवे (केबल कार) बनाई जाए।	Ropeways (RTDC)

	2. श्री हरदीप सिंह बावा, नालागढ़	
1.	क्षेत्र में कोटला कलां खडड, रेतड़ खडड तथा भटोली खडड पर बन रहे तीनों पुलों का निर्माण लगभग 70-80 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य को समय पर पूर्ण कर मार्च-अप्रैल में इनका उदघाटन कर दिया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2.	PMGSY के अधीन बनने वाली गोलजमाला-गुज्जरहट्टी सड़क, बरूना फलाई सड़क, पल्ली रेतड़ सड़क, रामशहर-कुवारनी-गब्बरमोड, गुज्जरहट्टी-पुरला-बनी पुरला-तलाउ-कंकलूघाट, सड़कों के कार्य चले हैं इन्हें शीघ्र निर्मित किया जाए। उपरोक्त सड़कों को पिछली भारी बरसात में ज्यादा नुकसान हुआ है। अतः इन सड़कों के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। इसके साथ-साथ ज्यूरा-गरलोह-जलनी सड़क का टैण्डर हो गया है इसे भी जल्द बनाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	वर्ष 2026-27 के लिए स्वारघाट-फगरेट-कोलाडूंगी प्लेट सड़क, लागत 12 करोड़ रू0, लम्बाई 11-12 कि0मी0 को विधायक प्राथमिकता में डाल रहा हूँ, इसका निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	नालागढ़ से रामशहर तथा रामशहर से गम्बरपुल सड़क पिछले मानसून में क्षतिग्रसत हुई है। निर्वाचन क्षेत्र में AMP का पैसा कम आता है इसे बढ़ाया जाए ताकि इन खराब सड़कों का उचित रख-रखाव किया जा सके।	लोक निर्माण विभाग
5.	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र के लिए घोषित की गई 10 सड़कों के निर्माण को कार्य शीघ्र आरम्भ / पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
6.	20 नं0 ट्यूबवैल की डी.पी.आर. को नाबार्ड से शीघ्र स्वीकृत करवाया जाए।	जल शक्ति विभाग
7.	क्षेत्र के लिए 20 नई बसें प्रदान की जाएं तथा चालकों और परिचालकों के चल रहे रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाए।	HRTC
8.	नालागढ़ क्षेत्र की रा0व0मा0 पाठशालाओं (Boys and Girls) में किसी एक पाठशाला को ही CBSE किया जाए तथा किसी एक पाठशाला को HPBOSE के अन्तर्गत ही रहने दिया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
9.	राजीव गॉंधी डे बोर्डिंग स्कूल निर्माण हेतु नंगल में 50 बीघा भूमि का चयन कर लिया गया है। इसे प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
10.	सी.एच.सी. नालागढ़ में चिकित्सकों के रिक्त चल रहे पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए तथा स्थानांतरित की गई गाईनी चिकित्सक को वापिस लाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
11.	पिछली आपदा में आंशिक रूप से प्रभावित हुए मकानों के लिए धनराशि आवंटित करने के मामले को जल्द निपटाया जाए।	राजस्व विभाग / उपायुक्त सोलन
	3. श्री राम कुमार, दून	
1.	चण्डी स्कूल को भी CBSE किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
2.	विधायक प्राथमिकता की डी.पी.आरज़ को तय समय पर (time bond) तैयार किया जाए।	लोक निर्माण / जल शक्ति/ सम्बन्धित विभाग
3.	SCDP के तहत बनी सडकों की मुरम्मत तथा रख-रखाव के लिए उचित बजट की व्यवस्था इसी बजट में की जाए।	ESOMA Deptt.
4.	वैलफेयर के तहत बन रहे मकानों के लिए अगली किश्त नहीं आ रही है इसे प्रदान किया जाए।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
5.	पट्टा-खडली-जतरोग सड़क पर खडली पुल के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर शीघ्र इसका निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
6.	बददी-साई लगभग 5 कि0मी0 सड़क के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर शीघ्र इसका निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	ISBT बस अडडा बददी का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए। इस बस अडडे का निर्माण हिमुडा द्वारा किया जाएगा। अतः निर्माण हेतु चयनित	बस अडडा प्राधिकरण/ HIMUDA

	भूमि को हाऊसिंग/ हिमुडा के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।	
8.	मिनी सचिवालय बददी का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए।	राजस्व विभाग
9.	निर्वाचन क्षेत्र में BBNDA के अधीन सड़कों की मुरम्मत तथा रख–रखाव के लिए BBNDA से धनराशि का प्रावधान कर शीघ्र इनकी मुरम्मत की जाए।	शहरी विकास/ लोक निर्माण/ उद्योग विभाग / BBNDA
10.	सी.एच.सी. चण्डी में डॉक्टरों के आवासीय भवन का निर्माण कार्य लगभग 80 प्रतिशत तक हिमुडा द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य पूर्ण करने के लिए 2.5 करोड़ वांछित धनराशि जारी कर कार्य पूरा किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ HIMUDA
11.	जल शक्ति विभाग के अन्तर्गत 14–15 ट्यूबवैलों का निर्माण 80–90 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य पूर्ण करने के लिए special fund की व्यवस्था की जाए।	जल शक्ति विभाग
12.	बददी सिवरेज लाईन बिछाने के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। इसके लिए ठेकेदार के बिलों के भुगतान समय पर किए जाएं।	जल शक्ति विभाग
13.	किशनगढ़ सब–तहसील को तहसील बनाने की रदद की गई अधिसूचना को पुनः बहाल किया जाए।	राजस्व विभाग
14.	कसौली तथा नालागढ़ डिवीजनों के अधीन सड़कों के लिए 50 कि0मी0 की AMP मिलनी चाहिए जोकि 14 कि0मी0 तथा 5 कि0मी0 ही आई है।	लोक निर्माण विभाग
15.	बरोटीवाला–बनलगी–शालाघाट सड़क All weather road निर्माण की डी.पी.आर. लगभग 215 करोड़ रू0 की तैयार है। नाबार्ड किटी में धनराशि कम होने के चलते इस डी.पी.आर. को World Bank से स्वीकृत करवाकर कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
16.	मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सड़कों के लिए बजट जारी कर निर्माण / मुरम्मत कार्य पूरे किए जाएं।	लोक निर्माण विभाग
17.	जल शक्ति विभाग बददी डिवीजन में Superintendent and Draftsman के पदों को भरा जाए।	जल शक्ति विभाग
18.	सी.एच.सी. पट्टा में चिकित्सकों के दो पदों के सृजित करने के मामले को शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर इन पदों को अविलम्ब भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
19.	बददी क्षेत्र के लिए नालागढ़ तथा बददी के सांझा HRTC बस डिपो के लिए 10 नई बसों का प्रावधान किया जाए।	HRTC
20.	बददी स्कूल (CBSE) के लिए वांछित 10–12 कमरों के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
21.	दून क्षेत्र में पड़ने वाली लगभग 10 कि0मी0 मंधाला–गुनाही सड़क को डबल लेन किया जाए, जिससे धर्मपुर तक डबल लेन की सुविधा क्षेत्र के लोगों को मिल जाए।	लोक निर्माण विभाग
22.	ग्रामीण सड़कों की मुरम्मत एवं रख–रखाव के लिए special budget का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण / ग्रामीण विकास/ पंचायती राज विभाग
	4. श्री विनोद सुल्तानपुरी, कसौली	
1.	छैला–ओच्छघाट–कुमारहट्टी सड़क निर्माण में कसौली क्षेत्र की जौहड़जी–मल्ला सड़क के भाग को जोड़ा जाए।	लोक निर्माण विभाग
2.	क्षेत्र की छोटी–छोटी ग्रामीण सड़कों (0.5 to 5 km approximately) के विस्तारीकरण / सुधारीकरण / सुदृढ़ीकरण की एक क्लब डी.पी.आर. (bunches of schemes) यदि बनाई जाए तो उसे नाबार्ड से स्वीकृत करवाने बारे विभाग कार्रवाई करे।	योजना विभाग
3.	उठाऊ पेयजल योजना गिरी नदी के रूके कार्य में 7 पाईपों को डालने के कार्य (लगभग 300 मीटर) को पंचायतों व स्थानीय लोगों द्वारा बार–बार रोका जा रहा है। पाईपों को शीघ्र बिछाया जाए और योजना का लाभ जनता को प्रदान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
4.	लोक निर्माण विभाग गरदौरी की सड़कों को अपने अधीन ले ताकि इनका उचित रख–रखाव हो सके।	राजस्व / लोक निर्माण विभाग

5.	जल शक्ति विभाग तथा विद्युत विभाग में तालमेल नहीं है जिस कारण पानी की तैयार योजनाएं चालू नहीं हो पा रही हैं। इन योजनाओं को चालू किया जाए।	जल शक्ति / विद्युत विभाग
6.	क्षेत्र के लिए दिए गये MSME Extension Centre को कोटबेजा के खाली पड़े भवन में चलाया जाए।	उद्योग विभाग/ शिक्षा विभाग स्कूल
7.	सुबाथु कॉलेज के लिए funds दिये जाएं।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
8.	पुलिस आवासीय परिसर धर्मपुर निर्माण हेतु 30 लाख की राशि जारी कर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए।	पुलिस विभाग
9.	कसौली सर्किट हाउस निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए 1.30 करोड़ रू0 जारी कर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
10.	धर्मपुर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन उपलब्ध करवाई जाए।	स्वास्थ्य विभाग
	5. जिला चम्बा	
	1. श्री हंस राज, चुराह	
1.	विधायक प्राथमिकता योजनाओं की डी.पी.आर्ज़ को शीघ्र तैयार किया जाए।	जल शक्ति / लोक निर्माण विभाग
2.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
3.	विद्युत विभाग के डिनोटिफाई डिवीजन को पुनः नोटिफाई किया जाए।	HPSEBLtd.
4.	बस अडडा चुराह का उदघाटन ऑनलाईन किया जा चुका है इसमें तारकोल बिछाने (पक्का करना) के शेष कार्य को पूर्ण किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
5.	जल शक्ति विभाग डिवीजन भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, इसका उदघाटन कर इसे चालू किया जाए।	जल शक्ति विभाग
6.	मिनी सचिवालय चुराह के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए बजट की उचित व्यवस्था की जाए और कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।	राजस्व विभाग
7.	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की निधि जारी की जाए।	योजना विभाग
8.	चम्बा मेडिकल कॉलेज का सुदृढ़ीकरण किया जाए। इसके साथ-साथ तीसा अस्पताल का भी सुदृढ़ीकरण किया जाए। तीसा अस्पताल में चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्टाफ नर्सो व अन्य तकनीकी व गैर तकनीकी पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
9.	पी.एच.सी. बैरागढ़ तथा कोहाल को डिनोटिफाई किया गया है इन्हें पुनः नोटिफाई किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
10.	हि0प्र0स्0शि0बोर्ड के स्कूलों को सी.बी.एस.ई. बोर्ड में न बदला जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
11.	पर्यटन की दृष्टि से एन.एच. द्रमण से वाया जोत, चम्बा, तीसा तथा पांगी सड़क को फोरलेन बनाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
12.	चम्बा से हैलीपोर्ट की सुविधा चालू की जाए।	पर्यटन विभाग
13.	चम्बा-तीसा मार्ग पर दो-तीन नऐ स्लाईडिंग प्वाईंटस बन गये हैं जैसे कि चांजू नाला, शरेला आदि इन स्लाईडिंग प्वाईंटस को ठीक करने के लिए धन का उचित प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
14.	चम्बा जिले में SPOs पिछले 25-26 वर्षो से काम कर रहे हैं इन्हें बटालियन में शामिल किया जाए।	पुलिस विभाग
	2. डॉ0 जनक राज, भरमौर	
1.	भरमौर निर्वाचन क्षेत्र के अधीन पड़ने वाले सभी विभागों में चल रहे रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	समस्त विभाग
2.	होली-उतराला सड़क की 21 करोड़ रू0 की डी.पी.आर. को नाबार्ड से स्वीकृत करवाया जाए। साथ ही इसमें बनने वाली सुरंगों का निर्माण पी.पी.पी. मोड़ पर किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
	3. श्री नीरज नैययर, चम्बा	
1.	चम्बा हैलीपोर्ट निर्माण कार्य 40-50 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया है। retaining wall निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि 4.74 करोड़ का प्रावधान किया जाए।	पर्यटन / लोक निर्माण विभाग
2.	मिनी सचिवालय चम्बा के निर्माण हेतु 29 करोड़ की धनराशि का प्रबन्ध कर निर्माण कार्य को पूरा किया जाए।	राजस्व विभाग

3.	निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर पंचायतें सड़क सुविधा सें वंछित हैं। यहॉं कुल मिलाकर 70 छोटी–2 सड़कों (1 से 1.5 कि0मी0 लगभग) का निर्माण होना है जिनके लिए एफ.सी.ए. मामले भी पूर्ण किए जा चुके हैं। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रत्येक सड़क में लगभग 25–50 लाख रू0 आने का अनुमान है। अतः जनहित में इन सड़कों का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	द्रडडा तथा सिडकुण्ड की 6 पंचायतों की पेयजल योजनाओं की डी.पी.आर. को नाबार्ड से स्वीकृत करवाया जाए।	जल शक्ति विभाग
5.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को 10–20 करोड़ रू0 बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
6.	Flood Protection के तहत जल शक्ति विभाग में 3 डी.पी.आर. State Disaster Mitigation में भिजवाई गई हैं, इन्हें जल्द स्वीकृत करवाया जाए।	राजस्व / जल शक्ति विभाग
7.	निर्वाचन क्षेत्र में पाइपों की कमी को दूर किया जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	चम्बा शहर की पार्किंग का टैण्डर लग चुका है इसके निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि लगभग 8 करोड़ रू0 की आवश्यकता है, इसे जारी किया जाए ताकि निर्माण कार्य पूर्ण हो सके।	शहरी विकास विभाग
9.	पुलिस लाईन के भीतर बन रहे ईन्डोर स्टेडियम का कार्य तीव्रगति से चला है इसे पूरा करने के लिए लगभग 7 करोड़ रू0 की राशि जारी की जाए ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके।	युवा खेल सेवाएं / पुलिस विभाग
10.	उदयपुर पंचायत में 16 बीघा भूमि का चयन प्राथमिक तथा व0मा0 राजीव गॉंधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण के लिए किया गया है। इसके टैण्डर के लिए उचित धनराशि का प्रावधान कर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ / पूरा किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
11.	चम्बा–चुवाड़ी सुरंग निर्माण कार्य को आरम्भ करने से पहले कांगड़ा तथा पठानकोट से आने वाले ट्रैफिक / यातायात के वाहनों की गणना / अध्ययन किया जाए ताकि सुरंग निर्माण के लिए चयनित केन्द्रों (points) में से किस केन्द्र बिन्दु से सुरंग का निर्माण प्रदेश हित / पर्यटन हित में लाभदायक हो के चयन में आसानी हो सके।	लोक निर्माण विभाग
12.	चम्बा मेडिकल कॉलेज के 200+300 कुल 500 बिस्तर का निर्माण एक ही जगह सरोल में किया जाए तथा स्वास्थ्य उपकरणों के टैण्डर कार्य को पूरा कर उपकरणों / मशीनों की खरीद जल्द की जाए, साथ ही रिक्त चल रहे विभिन्न श्रेणियों के पदों को अतिशीघ्र भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
13.	18 आउटसोर्स स्टॉफ नर्सों की नियुक्ति के टैण्डर कार्य को शीघ्र पूरा कर इनकी भर्ती अविलम्ब की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
	4. श्री डी0 एस0 ठाकुर, डलहौजी	
1.	बनीखेत सीवरेज स्कीम को शीघ्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	जल शक्ति विभाग
2.	क्षेत्र में बरसात के कारण काफी सड़कें खराब पड़ी हैं/ खस्ताहालत में हैं, इनकी मुरम्मत एवं रख–रखाव के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान कर इन्हें ठीक किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	बाथरी–सुंडला–सलूणी–लंगेरा सड़क के विस्तारीकरण का कार्य भारत सरकार के माध्यम से CRIF के तहत किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	PMGSY के तहत क्षेत्र की 3–4 सड़कों के FCA के मामलों का निपटान शीघ्र किया जाए ताकि इन सड़कों का निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके और स्थानीय जनता को इनका लाभ मिल सके, जैसे कि नडडल से जतराहन, सकोटी सड़क इत्यादि।	लोक निर्माण विभाग
5.	निर्वाचन क्षेत्र डलहौजी में विद्युत व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए लगभग 38 करोड़ रू0 भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इसके तहत हो रहे कार्य धीमीगति से चले हुए हैं इन्हें तीव्रगति से गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।	HPSEBLtd.
6.	आपदा में चौड़ा गॉंव से ऊपर की भूमि धँस रही है / प्राकृतिक भूमि कटाव हो रहा है जिससे पूरे गॉंव को खतरा पैदा हो गया है। इस सम्बन्ध में यहॉं के निवासियों को NHPC की waste land या अन्य स्थान पर 3–4	राजस्व विभाग / उपायुक्त चम्बा

	बिस्वा भूमि प्रदान की जाए ताकि वहाँ पर यह लोग सुरक्षित जीवन यापन कर सकें।	
7.	नागरिक अस्पताल सलूणी तथा किहार में एम.ओ. के रिक्त पदों के साथ–साथ आउटसोर्स स्टॉफ नर्सों और फॉर्मासिस्ट के रिक्त चल रहे पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
8.	मेडिकल कॉलेज चम्बा शहर के क्षेत्रीय अस्पताल को नीचे एक ही स्थान पर सरोल में स्थानांतरित किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
9.	पर्यटन की दृष्टि से सुभाष चौक से गंजी पहाड़ी तक रोपवे का निर्माण किया जाए।	Ropeways (RTDC)
10.	नाबार्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाने वाली डी.पी.आर्ज. को माननीय विधायक की संस्तुति (approval / permission) उपरान्त ही भेजा जाए ताकि जरूरी / अति आवश्यक डी.पी.आर्ज. को पहले नाबार्ड को प्रेषित किया जा सके।	योजना विभाग
11.	ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करने के लिए सलूणी में कृषि तथा उद्यान विभाग के कार्यालयों में चल रहे रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	कृषि / उद्यान विभाग
12.	विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं / स्कीमों के लिए धनराशि ट्रैजरी से समय पर जारी की जाए।	कोषागार / योजना विभाग
	6. जिला बिलासपुर	
	1. श्री जीत राम कटवाल, झण्डूता	
1.	लोक निर्माण विभाग की नाबार्ड को प्रेषित 5 डी.पी.आर्ज़ को शीघ्र स्वीकृत करवाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2.	निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों रू0 की लागत से 9 पुलों का निर्माण हुआ है जैसे बागछाल, नन्दग्रां आदि। 100 मीटर, 52 मीटर तथा 76 मीटर लम्बे पुलों के सड़क एपरोचिज़ के कार्य पिछले तीन वर्षों से लम्बित हैं, इन्हें शीघ्र पूरा किया जाए, जैसे री, रंडोह, डुग, दसलेहड़ा खमेड़ा कलां इत्यादि।	लोक निर्माण विभाग
3.	छमाहण–बैहना जटटां–बिलासपुर सुरंग निर्माण की डी.पी.आर. शीघ्र तैयार की जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	बैरी दड़ोलां पुल निर्माण की डी.पी.आर. तैयार की जाए।	लोक निर्माण विभाग
5.	ज्योरिपतन–स्वारघाट रोपवे का निर्माण किया जाए।	Ropeways (RTDC)
6.	भाखड़ा डैम से पानी उठाने वाली कुट बांगडू योजना के कार्य को तीव्रगति से गुणवत्ता के साथ आरम्भ/पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
7.	2200 है0 क्षेत्र को सिंचित करने वाली सीर खडड पर डैम बनाने की डी. पी.आर. को शीघ्र केन्द्र से स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	एम.डी.आर. बागछाल–शाहतलाई सड़क की डी.पी.आर. को केन्द्र से स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
9.	कासर्वी सिंचाई / पेयजल योजना की मोटरें काम नहीं कर रही हैं, इनका सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए।	जल शक्ति विभाग
10.	निर्वाचन क्षेत्र के लिए SCDP के तहत उचित धनराशि प्रदान की जाए।	ESOMA Deptt.
	2. श्री त्रिलोक जम्वाल, बिलासपुर	
1.	भन्जवानी पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2.	बिलासपुर शहर की सीवरेज योजना का कार्य जिस कम्पनी द्वारा किया जा रहा है उन्हें निर्देश दिए जाएं कि शहर की सड़क के जिस हिस्से में सीवरेज लाईन बिछा दी जाए उसी दौरान उस हिस्से की मैटलिंग / टारिंग का कार्य भी कर दिया जाए।	शहरी विकास/ जल शक्ति / लोक निर्माण विभाग
3.	क्षेत्र में विद्युत विभाग से सम्बन्धित कार्यों (RDSS) को तीव्रगति से गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, जैसे ट्रांसफॉर्मर लगाना, खम्बे लगाना, तारें डालना, केबलिंग इत्यादि तथा नंगी तारों की केबलिंग की जाए।	HPSEBLtd.
4.	केन्द्रीय सहायता से बनने वाली सोर–मंदरीघाट–जबलयाणा सड़क 16 करोड़ रू0 की लागत से बन रही है, इसका कार्य पिछले 5–6 साल से धीमी	लोक निर्माण विभाग

	गति से चला है, इस सड़क निर्माण कार्य को तीव्रगति से गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।	
5.	भानुपली–बिलासपुर–बैरी रेल लाईन में पूर्ण भूमि अधिग्रहण किया जाए और निर्माण कार्य को पूरा किया जाए।	परिवहन विभाग(रेलवे)
6.	गोविन्दसागर तथा कोलडैम रिजरवायर में स्पोर्टज़ एक्टीविटी (जलक्रीड़ाएं) चलाई जाएं। खासकर कोलडैम में पर्यटन गतिविधियों को आरम्भ किया जाए।	युवा खेल सेवाएं/ पर्वतारोहण खेल संस्थान/पर्यटन विभाग
7.	बेसहारा पशुओं और जंगली जानवरों सें फसलों को बचाने के लिए नई पॉलिसी (जालीदार तार 8–10 फुट ऊंची) लगाई जाए।	कृषि / उद्यान विभाग
8.	फोरलेन पर भराड़ी पुल के पास बस स्टैण्ड का निर्माण किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
9.	नालागढ़–बददी–किरतपुर फोरलेन का कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
10.	भटोली पानी की योजना के शेष 5 प्रतिशत कार्य को पूर्ण करने के लिए 10–12 लाख रू0 की धनराशि का प्रावधान किया जाए ताकि योजना को चालू किया जा सके और क्षेत्र की 10–12 पंचायतों को इसका लाभ मिल सके।	जल शक्ति विभाग
11.	मुख्यमंत्री लोक भवन कन्दरौर तथा कुठेड़ा का कार्य लगभग 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है, शेष 5 प्रतिशत कार्य को पूर्ण करने के लिए उचित धनराशि का प्रावधान कर निर्माण कार्य पूरा किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
12.	क्षेत्र में Rehabilitation Centre का निर्माण किया जाए या जिला अस्पताल के 4–6 कमरों में Rehabilitation Centre चलाया जाए।	स्वास्थ्य / पुलिस विभाग
13.	जिला बिलासपुर में एक ऐसा कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर पुलिस विभाग के अधीन चलाया जाए जिसमें बाहरी राज्यों से जिला बिलासपुर में भराड़ी पुल और नौणी से प्रवेश करने वाले संदिग्ध वाहनों की मॉनिटरिंग तथा जॉच हो सके ताकि आपराधिक गतिविधियों (चिटटे के नशे की जॉच / लूट मार / अन्य आपराधिक घटनाओं की रोक हेतु) को रोका जा सके।	पुलिस विभाग
14.	अमरसिंहपुरा सड़क के लिए आधे बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया जाए, यदि आवश्यक हुआ तो माननीय विधायक इसके लिए अपनी विधायक निधि से धनराशि का प्रावधान भी कर सकते हैं।	लोक निर्माण विभाग
15.	विधायक क्षेत्र विकास निधि की किश्त जारी की जाए।	योजना विभाग
	3. श्री रणधीर शर्मा, श्री नैनादेवी जी	
1.	स्वाहन से कटीरड़–पंगवाना सड़क की डी.पी.आर. को नाबार्ड से शीघ्र स्वीकृत करवाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2.	PMGSY-IV के तहत लगभग 35 सड़कें निर्वाचन क्षेत्र के लिए आई हैं। इन सड़कों की डी.पी.आर. तैयार करने के लिए उपायुक्त महोदय से मिलने वाला non availability of non forest land व अन्य प्रमाण पत्र एकमुश्त जारी किए जाएं, ताकि इन सड़कों की डी.पी.आर. को समय पर तैयार किया जा सके।	लोक निर्माण विभाग / उपायुक्त बिलासपुर
3.	लोक निर्माण विभाग तथा वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मिलकर (Joint Inspection) एफ.सी.ए. के मामलों का निपटान समय पर (Time Bound) किया जाए। इसके साथ–साथ एफ.सी.ए. के मामलों का निपटान पहले क्षेत्रीय कार्यालय में किया जाता था जो अब पुनः केन्द्र द्वारा किया जा रहा है, इस बारे भारत सरकार से मामला उठाया जाए।	लोक निर्माण / वन विभाग
4.	नवगॉव–बैरी सड़क को भारत सरकार के CRIF में 80 करोड़ रू0 आये थे जिसमें 19 करोड़ रू0 की बचत है। इस सड़क पर बागा क्षेत्र की 4–5 कि0मी0 सड़क के बचे कार्य को इस बचत की राशि से पूरा किया जाए, क्योंकि इस सड़क की हालत ठीक नहीं है और सीमेंट कम्पनी वाले इसे नहीं बना रहे हैं।	लोक निर्माण विभाग
5.	DMFT का पूरा पैसा जिला सोलन में दिया जाता है इसका कुछ हिस्सा जिला बिलासपुर को भी प्रदान किया जाए।	उद्योग / खनन विभाग
6.	जल शक्ति विभाग के सब–डिवीजन जुखाला में विभिन्न पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कोलडैम से उठाऊ पेयजल योजना की लगभग 93	जल शक्ति विभाग

	करोड़ रू0 की डी.पी.आर. को भारत सरकार के माध्यम से शीघ्र स्वीकृत कर कार्य आरम्भ किया जाए।	
7.	निर्वाचन क्षेत्र के अधीन जल शक्ति विभाग में Field Staff के रिक्त चल रहे पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	निर्वाचन क्षेत्र के अधीन विद्युत विभाग में Field Staff के रिक्त चल रहे पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	HPSEBLtd.
9.	निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर हर गाँव, हर घर के लिए 3-फेज लाईन का प्रबन्ध किया जाए। साथ ही इस योजना को पूरे प्रदेश में चलाया जाए।	HPSEBLtd.
10.	गाँव, शहर या किसी भी अन्य स्थान पर लोगों को अपनी भूमि से बिजली के खम्बे, तारें स्थानांतरित करने में पेरशानी आ रही है, विभाग के पास न तो पैसा है न ही पूरा स्टाफ है। इसलिए इस कार्य पर आने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि से प्रावधान किया जाए।	योजना विभाग / HPSEBLtd.
11.	नागरिक अस्पताल नैनादेवी के भवन के अधूरे निर्माण कार्य को उचित धनराशि की व्यवस्था कर शीघ्र पूरा किया जाए।	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
12.	नैनादेवी मन्दिर में लिफ्ट लगाने के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।	भाषा कला एवं संस्कृति विभाग / उपायुक्त बिलासपुर
13.	Intensive Care Unit नैनादेवी जी के भवन निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
14.	किरतपुर-बिलासपुर फोरलेन बनने के बाद पुराने रूट पर 4-5 गाँव के लोगों की सुविधा के लिए बसों को चलाया जाए।	HRTC
15.	विधायक क्षेत्र विकास निधि की किश्त को जारी किया जाए।	योजना विभाग
	7. जिला लाहौल-स्पिति	
	1. कुमारी अनुराधा राणा, लाहौल-स्पिति	
1.	लाहौल स्पिति को हैली टैक्सी सेवा से जोड़ा जाए।	पर्यटन विभाग
2.	लाहौल व स्पिति को जोड़ने वाली सड़क मार्ग जो बी.आर.ओ के अधीन है, कुंजुम टॉप पर सुरंग निर्माण किया जाए ताकि पूरे वर्ष स्पिति व लाहौल मुख्यालय आपस में जुड़ा रहे। तथा यह क्षेत्र भारी बर्फबारी में भी न कटे और यातायात भी सुचारू हो सके।	लोक निर्माण विभाग
3.	माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा लाहौल में हैलीपोर्ट निर्माण को जल्द अमलीजामा पहनाया जाए।	पर्यटन विभाग
4.	Polytechnic कॉलेज लाहौल-स्पिति के नाम से पिछले 10 वर्षों से सुन्दरनगर में चल रहा है इसे लाहौल में स्थानांतरित किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
5.	राजीव गाँधी डे-बोर्डिंग में क्षेत्र के तीन स्कूलों का चयन किया गया है, इनका शीघ्र सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
6.	मुदभावा-लियो bypass सड़क को बी.आर.ओ. के अधीन लाकर इसका निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/ पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	जनजातीय जिलों में मिनी बसों तथा टैम्पो ट्रैवलर की उचित व्यवस्था कर इनका सुचारू संचालन किया जाए।	HRTC
8.	भारी बरसात तथा आपदा से क्षेत्र की सिंचाई, पेयजल योजनाओं तथा सड़कों को नुकसान हुआ है, इसलिए SDRF तथा NDRF के तहत अधिक बजट की व्यवस्था जनजातीय क्षेत्रों के लिए की जाए ताकि इन प्रभावित योजनाओं को ठीक किया जा सके।	राजस्व विभाग
9.	क्षेत्र में किसी भी विभाग द्वारा जब किसी बड़ी बैठक का आयोजन विकास योजनाओं / समस्याओं के समाधान हेतु या किसी अन्य सम्बन्ध में किया जाता है तो सम्बन्धित विधायक को उस बैठक में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाए, क्योंकि स्थानीय विधायक को अपने क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं/जरूरतों का पता होता है।	समस्त सम्बन्धित विभाग
10.	जालमा नाला में भारी बरसात के दौरान आई बाढ़ से क्षेत्र की 5 पंचायतें प्रभावित हुई हैं। विशेषकर लिन्डूरे गाँव जो लगातार धंस रहा है को बचाने के लिए इनका restoration का कार्य Disaster Mitigation Fund से किया जाए।	जल शक्ति / राजस्व विभाग विभाग

	इसके साथ–साथ जालमा नाला प्रोजेक्ट कार्य को स्वीकृत कर कार्य आरम्भ किया जाए ताकि और गाँवों को प्रभावित होने से बचाया जा सके।	
11.	जनजातीय क्षेत्रों में होटलों तथा होमस्टे के निर्माण / renewal के लिए Fire NOC जारी करने की शर्तो तथा नियमों में छूट प्रदान की जाए।	पर्यटन विभाग
12.	जनजातीय क्षेत्रों में जो भी M.O. 20 प्रतिशत कोटे से P.G. करते हैं उन्हें 2–3 साल उसी क्षेत्र में सेवाएं देने बारे विभाग उचित पॉलिसी निर्माण करे।	स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा विभाग
13.	क्षेत्र के स्कूलों में मेडिकल तथा नॉन मेडिकल के प्राध्यापकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए या माननीय मुख्यमंत्री के सुझाव को अमलीजामा पहनाया जाए कि इस क्षेत्र के बच्चों को किसी अन्य स्थान के अच्छे बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल की सुविधा के साथ शिक्षा की व्यवस्था की जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/स्कूल)
14.	केलांग तथा स्पिति के अस्पतालों में गाईनी विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति अतिशीघ्र की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
15.	लाहौल में स्टेडियम निर्माण किया जाए ताकि आईस हॉकी तथा आईस स्केटिंग के खेलों में स्थानीय युवा भाग लेकर प्रदेश का नाम रोशन करें।	युवा खेल सेवाएं विभाग
16.	निर्वाचन क्षेत्र की कच्ची सड़कों को पक्का किया जाए तथा इसके लिए विशेष धन का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
17.	जल शक्ति विभाग में सिंचाई / पेयजल की निर्माणाधीन तथा अधूरी योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए, इसके लिए धन की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
18.	PMGSY के तहत सड़कों के चयन में Population Criteria (250 person) के नियमों में छूट प्रदान करने बारे भारत सरकार से मामला उठाकर इसमें छूट दिलाई जाए, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र लाहौल–स्पिति भौगोलिक रूप से तो बड़ा है लेकिन जनसंख्या में छोटा है।	लोक निर्माण विभाग
19.	क्षेत्र के लिए उपलब्ध करवाई गई मशीनें जैसे जे.सी.बी., स्नो कटर इत्यादि खराब चल रही हैं, इनकी जगह नई तकनीक की नई मशीनों का प्रबन्ध किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
20.	स्पिति में कॉलेज का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/स्कूल)
21.	क्षेत्र में कार्य करने के लिए श्रेणी तृतीय तथा चतुर्थ हेतु Tribal Sub Cadre या Roster पहले की तरह जारी किया जाए।	समस्त सम्बन्धित विभाग
22.	बी.पी.एल. चयन प्रक्रिया में आयु सीमा की छूट जो वर्तमान में 27–59 की गई है इसमें छूट दी जाए या पहले की तरह (18–59) किया जाए।	पंचायती राज विकास/ ग्रामीण विकास विभाग
23.	लाहौल तथा स्पिति में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाए, जिसमें एक की आधारशिला को लगभग 10 वर्ष पहले रखी जा चुकी है।	राजस्व विभाग
	8. जिला कुल्लू	
	1. श्री भुवनेश्वर गौड़, मनाली	
1.	मनाली में आईस स्केटिंग रिंक का कार्य आरम्भ किया जाए।	
2.	डी.पी.आरज. की limit exhaust होने के कारण विभागों को वापिस की गई है। क्योंकि अब limit बढ़कर 200 करोड़ रूपये हो गई है तो इस स्थिति में उन डी.पी.आरज. को फिर से consider किया जाए। डी.पी.आर. जैसे कि नेहरू कुण्ड पुल से मोशाल गाँव तक सड़क निर्माण लागत मु0 860.64 लाख रू0 प्राथमिकता–।। वर्ष 2022.23. ।	लोक निर्माण विभाग
3.	वर्ष 2023–2024 की नाबाड़ को स्वीकृति हेतु प्रेषित मु0 1216.96 लाख रू0 की डी0पी0आर0 M/T on link road Soil to Tangling को नाबार्ड से Withdraw किया जाए, क्योंकि यह डी.पी.आर. PMGSY-IV में आ चुकी है।	लोक निर्माण विभाग
4.	मनाली Left Bank Road के मुरम्मत कार्यो को CRIF Fund के अर्न्तगत किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
5.	सी0एच0सी0 पतलीकुहल में चिकित्सक के पद को सृजित किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
6.	दुर्गम गांव झीना में एक उप–स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए।	स्वास्थ्य विभाग

7.	मनाली वोल्वो बस स्टैंड़ की दिवारों के Flood protection के restoration के कार्यों को शीघ्र किया जाए तथा इस कार्य के लिए Tourism Dev. corporation का पैसा खर्च किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
8.	वॉलवो बस स्टैण्ड से होने वाली आय में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी Tourism Dev. corporation को भी प्रदान की जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
9.	मनाली की तंग गलियों की सड़कों से बर्फ हटाने के लिए Bobcart machine की उचित व्यवस्था की जाए।	लोक निर्माण विभाग
	2. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, कुल्लू	
1.	PMGSY-IV में जो सड़कें आई हैं उन सड़कों के कार्य को समय पर किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2.	मणिकर्ण को जाने के लिए अलग से 30-35 कि0मी0 वैकल्पिक सड़क मार्ग का निर्माण किया जाए (Parvati river left bank)।	लोक निर्माण विभाग
3.	भुभु सुरंग निर्माण कार्य को गति प्रदान की जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	घटासनी-शिलाबधाणी, कुल्लु-बड़ोण सड़क को फोरेलेन बनाया जाए तथा बोथ साईड एपरोचिज़ की जाए।	लोक निर्माण विभाग
5.	कुल्लू-मनाली एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए।	पर्यटन विभाग
6.	मातृ-शिशु अस्पताल कुल्लू में चिकित्सकों तथा रेडियोलॉजी के पद को सृजित किया / भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
7.	आदर्श स्वास्थ्य संस्थान तेगुबेड़ में चिकित्सकों व अन्य स्टॉफ के रिक्त पदों को भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
8.	कुल्लू अस्पताल में मनोवैज्ञानिक रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
9.	प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाले पर्यटन एक्सपो (Tourism events) में हिमाचल प्रदेश का पर्यटन विभाग हिस्सा ले, जिससे हिमाचल प्रदेश को अलग पहचान मिल सके।	पर्यटन विभाग
10.	व्यास नदी की ड्रेजिंग के कार्य को शीघ्र आरम्भ किया जाए।	उद्योग/जल शक्ति विभाग
11.	बिजली महादेव रोपवे परियोजना का फिर से रिव्यू / अध्ययन किया जाए।	Ropeways (RTDC)
12.	कुल्लु के होला मोहल्ला में लॉ एण्ड ऑर्डर को ठीक करने के लिए QRT लगाई जाए तथा इस टीम में कमाण्डो लगाए जाएं।	पुलिस विभाग
13.	पुलिस स्टेशन मणिकर्ण एट कसोल में पूरा स्टाफ प्रदान कर इसे चालू किया जाए।	पुलिस विभाग
	3. श्री सुरेन्द्र शौरी, बंजार	
1.	विधान सभा क्षेत्र बंजार की नाबार्ड को प्रेषित 4 सड़कों की डी.पी.आर्ज़ को शीघ्र स्वीकृत करवाया जाए। इसमें मुख्यतः वाहँ से वियों व डुलीनाल से भूमार अति आवश्यक है।	लोक निर्माण विभाग
2.	बंजार तथा सेंज आदि क्षेत्रों में बिजली की कमी की बहुत समस्या है इसे दूर किया जाए।	HPSEBLtd.
3.	बजौरा विद्युत सब-स्टेशन का सुदृढ़ीकरण किया जाए।	HPSEBLtd.
4.	एन.एच.- 305 औट से लूहरी सड़क की हालत बहुत खराब है, इसकी दयनीय स्थिति को ठीक किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
5.	पर्यटन की दृष्टि से लारजी में वॉटर स्पोर्टस की गतिविधियों को आरम्भ किया जाए।	Mountaineering Allied Sports / पर्यटन विभाग
6.	आदर्श अस्पताल बंजार के भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
7.	भुंतर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए।	पर्यटन विभाग
8.	भारी बरसात के चलते भविष्य में आपदा को कम करने हेतु क्षेत्र के पुराने नालों का तटीयकरण (channelization) खडडों तक जल शक्ति विभाग के माध्यम से इस तरह किया जाए कि नालों का पानी सीधे खडडों में जाए। साथ ही नए नालों का भी निर्माण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
	4. श्री लोकेन्द्र कुमार, आनी	
1.	नगर क्षेत्र आनी के तटीयकरण(channelization) की डी.पी.आर. को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।	जल शक्ति विभाग

2.	क्षेत्र के लोगों को दूध की payments की जाए।	HP Milkfed
3.	आदर्श अस्पताल आनी में एक्सरे की मशीन लगाई जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	समेज खडड में आई बाढ़ से प्रभावित तीन परिवारों को जल्दी मुआवजा प्रदान किया जाए।	राजस्व विभाग /उपायुक्त कुल्लू
5.	आदर्श स्वास्थ्य संस्थान से नर्सों का डेपयुटेशन / स्थानांतरण बन्द किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
6.	चिट्टे के नशे की समस्या को जड़ से समाप्त किया जाए, इसके लिए आनी पुलिस बल में बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ–साथ यातायात के सुचारू संचालन के लिए ट्रैफिक की अलग से विंग खोली जाए।	पुलिस विभाग
7.	निर्वाचन क्षेत्र में सेब व अन्य फसलों को ओलों से बचाने के लिए एन्टी हेलगन या इससे उन्नत नई तकनीक उपयोग में लाई जाए।	कृषि / उद्यान विभाग
8.	आपदा प्रभावित क्षेत्र कोयल तथा केदस के लिए mitigation की धनराशि उपलबध करवाई जाए।	राजस्व विभाग
9.	बायल तथा कोयल में सैंकड़ों बीघा भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए।	जल शक्ति विभाग
10.	PMGSY में जो सड़कें आई हैं उन सड़कों के कार्य को समय पर किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
11.	आपदा में ज्वागी तथा चायल पंचायतों में छोटे–2 पुलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या बड़े खतरे के साथ यहाँ से गुजरते हैं। अतः इन टूटे / क्षतिग्रस्त पुलों को पुनः निर्मित किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
12.	कुल्लू से आनी–शिमला बस सेवा को चालू किया जाए।	HRTC
13.	बाणु स्कूल तथा लगोटी स्कूल को बरसात में भारी नुकसान हुआ है। अतः इन स्कूलों को पुनः निर्मित करने के लिए धनराशि का उचित प्रबन्ध किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/स्कूल)
	9. जिला मण्डी	
	1. श्री दीप राज, करसोग	
1.	CRIF के तहत बनने वाली बखरोल–सनारली–कोटलू सड़क के एफ.सी.ए. मामले को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि लोक निर्माण विभाग समय पर इस सड़क का टैण्डर लगा सके।	लोक निर्माण / वन विभाग
2.	PMGSY की सड़कों के निर्माण के लिए यदि कोई व्यक्ति मुश्तरका खाता, के.सी.सी. मामले आदि होते हुए भी यदि गिफ्ट डीड के माध्यम से अपनी भूमि से कुछ जमीन सड़क निर्माण में देना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे उस दान की जाने वाली भूमि के हिस्से के लिए अनापत्ति जारी करने की शर्तों में छूट (relaxation) प्रदान की जाए।	राजस्व विभाग
3.	ITI करसोग के भवन को पूरा करने के लिए धन की उचित प्रावधान किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
4.	पॉलटेक्निक कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ / पूरा किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
5.	पुलिस स्टेशन के भवन निर्माण के कार्य को पूर्ण किया जाए।	पुलिस विभाग
6.	ग्रामीण क्षेत्रों में बन्द पड़े रूटों पर बसे चलाई जाएं।	HRTC
	2. श्री राकेश कुमार, सुन्दरनगर	
1.	सी.एच.सी. नीरी तथा पी.एच.सी. बलग के भवन निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।	स्वास्थ्य / लोक निर्माण विभाग
2.	नागरिक अस्पताल सुन्दरनगर में चिकित्सकों व पैरामैडिकल स्टाफ के लिए आवास निर्माण के कार्य को जल्दी पूरा करे।	स्वास्थ्य विभाग
3.	नीरी क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को हल किया जाए।	जल शक्ति विभाग
4.	डैहर क्षेत्र में पीने के पानी की जो योजना बनी है उसमें सुधार की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र की पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सके।	जल शक्ति विभाग
5.	सुन्दरनगर शहर के लिए एक नई सीवरेज योजना बनाई जाए।	जल शक्ति विभाग
6.	ITI डैहर के भवन का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, अतः शेष कार्य को पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग

7.	पौड़ाकोठी तथा तलेली रा०व०मा० पाठशालाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/स्कूल)
8.	विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत नीरी से चरखड़ी सड़क की डी.पी.आर. जो कि नाबार्ड के स्वीकृति हेतु विचाराधीन है को शीघ्र स्वीकृत करवाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
9.	सुन्दरनगर शहर में बी.बी.एम.बी. द्वारा निर्मित पुल के साथ-साथ एक और पुल का निर्माण बीबीएमबी के साथ मिलकर किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
10.	इन्डोर स्टेडियम सुन्दरनगर का कार्य पूर्ण हो चुका है, केवल फलोरिंग तथा पैनलिंग का कार्य होना शेष है। अतः इस कार्य को पूर्ण करने हेतु पूरी धनराशि की व्यवस्था कर कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।	युवा खेल सेवाएं विभाग
11.	विधायक क्षेत्र विकास निधि की लम्बित किश्त को जारी किया जाए।	योजना विभाग
12.	विधायक ऐच्छिक निधि की लम्बित किश्त को जारी किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
13.	सुन्दरनगर क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के निर्माणाधीन रैस्ट हाउस के 20 प्रतिशत शेष कार्य को पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
	3. श्री विनोद कुमार, नाचन	
1.	भारी बरसात के कारण ग्राम पंचायत सियांज के बागा, सरवागड़ा, मजगाहन, कनापड़ी और छोल के पैदल पुलों (Foot Bridges) को अभी तक निर्मित नहीं किया गया है इन्हें जनहित में शीघ्र बनाया (Restore) जाए।	वन/ पंचायती राज/ लोक निर्माण विभाग/ उपायुक्त
2.	लोक निर्माण विश्राम गृह धनोटू का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है इसका उदघाटन कर इसे चालू किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	रा०व०मा० पाठशालाएं मौंवीं सेरी तथा किर्लींग में साईंस लैब निर्माण हेतु टैण्डर लगाए जाएं तथा इनके निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
4.	क्षेत्र के डिग्री कॉलेज के ईन्डोर स्टेडियम का निर्माण ठेकेदार के माध्यम से शीघ्र करवाया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
5.	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सड़क ''M/T of road Jatta Ra Nala to Kuledigalu via H.B Saloun, Katloun & Chhamyar'' का निर्माण कार्य जल्दी आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
6.	चेलचौक वाया देवीदड़ शिकारी देवी सड़क को CRIF में डाला जाए और इसके लिए इसे पहले MDR रोड़ घोषित किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	पंडोह से चेलचौक तक सड़क की DPR को CRIF के तहत स्वीकृत करवाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8.	मंड़ी-गागल-चेलचौक-जंजहैली सड़क के Rehabitation का कार्य जिसे CRIF के अंतर्गत मंजूरी मिली है उसमें बग्गी से चेलचौक तक सड़क का नाम भी जोड़ा जाए।	लोक निर्माण विभाग
9.	जल शक्ति विभाग की निर्मित योजनाओं को चलाने के लिए बिजली के Transformer लगाए जाएं।	जल शक्ति विभाग/ HPSEBLtd.
10.	नाचन विधानसभा क्षेत्र को आपदा राहत के लिए कम धन प्राप्त हुआ है, इसे दिया जाए।	राजस्व विभाग
11.	SDP और विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा दिया जाए।	योजना विभाग
12.	हिमकेयर योजना के अंतर्गत कार्ड बनाए जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
	4. श्री पूर्ण चन्द ठाकुर, द्रंग	
1.	भारी बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए बचे हुए पात्र व्यक्तियों तक भी राहत राशि पहुंचाई जाए। एक व्यक्ति डूनेराम का मकान ध्वस्त हुआ है, उसे मात्र 70 हजार ही मिले हैं। शेष राशि का भुगतान अतिशीघ्र किया जाए।	राजस्व विभाग
2.	विधानसभा क्षेत्र के शनोर इलाके की देवखान-शाला-बनोगी सड़क की हालत बहुत खराब है यहां HRTC की बस 7 महीनों से बंद पड़ी है, इस सड़क की हालत को सुधारा जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	नाऊ-काशना सड़क बंद पड़ी है इसे खोला जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	नाऊ-काशना वाया टेपर राढ़ी सड़क 7 महीनों से बन्द पड़ी है इसे खोला जाए।	लोक निर्माण विभाग
5.	थलोट-जला-चटोगी-जलाकाशना की 10 कि०मी० सड़क बन्द पड़ी है इसे जनहित में शीघ्र खोला जाए।	लोक निर्माण विभाग
6.	बलोह ले जाए गऐ PWD Division को दुबारा थलोट में खोला जाए।	लोक निर्माण विभाग

7.	पेयजल योजना झीड़ी से कथयाली पंचायत तक का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, अतः 10 प्रतिशत कार्य भी जल्दी करवाया जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	राजकीय वरिष्ट माध्यमिक पाठशाला टिहरी के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए शेष धनराशि मात्र 10 लाख रुपये की आवश्यकता है, अतः इसे शीघ्र प्रदान किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
9.	BASP के अंर्तगत निर्मित सड़कें जिनका उदघाटन कर लिया गया है उनमें Buses को चलाया जाए।	HRTC/ लोक निर्माण विभाग
10.	क्षेत्र में फोर–लेन का कार्य संतोषजनक नहीं है। इलाके में हो रही कटिंग से मकानों को नुकसान हो रहा है। इस बारे उचित कार्रवाई की जाए।	लोक निर्माण विभाग
11.	PMGSY-III के अंर्तगत स्वीकृत सड़कों के Tender लगाए जाए।	लोक निर्माण विभाग
12.	2017 में ज्वालापुर Primary Health Centre (PHC) का शिलान्यास किया गया था, परन्तु अभी तक इसका निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है। अतः क्षेत्र की जनता के हित के लिए इसका Tender शीघ्र लगाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
	5. श्री प्रकाश राणा, जोगिन्द्रनगर	
1.	भारी बरसात की आपदा में क्षेत्र में अभी भी कई गांव की सड़कें बंद है, इन्हें खोला जाए। वर्ष 2023 के बाद पक्की सडकों की टायरिगं नही हुई है, इसे भी करवाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2.	जोगिन्द्रनगर विधानसभा का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होने के नाते इस क्षेत्र में सड़कों आदि के विकास के मामले में अलग योजना की आवश्यकता है। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से योजनाओं का युक्तिकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	बसी–मनोह–नैर घुवासड़ा, फागला–माकन आदि रोड़ बन्द पड़े हैं उसमें डंगे लगाने पड़ेगें ताकि ग्रामीण जनता को लाभ मिल सके। इन्हें जल्दी ठीक किया जाए। और बरसात के बाद बन्द पड़ी सड़कों को जल्दी खोला जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	Optical Fibre बिछाने की ऐवज में 85 कि0मी0 रोड़ को 6 फीट गहरा व चार फीट चौड़ा वह भी दीवार के साथ खोदा गया, परन्तु उसमें नालियां अभी भी नहीं बनी हैं। बरसात के दौरान इससे साथ लगते इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। अतः नालियों का काम जन्दी पूरा किया जाये।	लोक निर्माण विभाग
5.	जल शक्ति विभाग की योजनाओं को बरसात के कारण आई आपदा से बहुत नुकसान हुआ है। पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हुई है। इन्हें जल्दी ठीक किया जाए।	जल शक्ति विभाग
6.	विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की जितनी भी स्कीमें हैं, जिनमें 90 प्रतिशत काम हो चुका है, इनमें बचे 10 प्रतिशत कार्य को पूरा करने के लिए पैसा दिया जाए।	जल शक्ति विभाग
7.	क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की बहुत समस्या है इसे जल्दी ठीक किया जाए।	HPSEBLtd.
	6. श्री चन्द्र शेखर, धर्मपुर	
1.	धर्मपुर–जोगिन्द्रनगर को जोड़ने वाले लाल बहादुर शास्त्री सेतु के लिए धन का प्रावधान किया जाये।	लोक निर्माण विभाग
2.	कमलाह धरौन पुल का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु धन का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	संधोल में तहसील कल्याण कार्यालय खोला जाएं	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4.	टिहरा को तहसील बनाया जाए।	राजस्व विभाग
5.	सब–डिवीजन आर्युवेदा कार्यालय खोला जाए।	आयुष विभाग
6.	धर्मपुर, संधोल और टिहरा अस्पतालों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन मशीनें हैं, इनमें संचालन की व्यवस्था की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
7.	संधोल तथा टिहरा अस्पतालों में महिला विशेषज्ञ प्रदान की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
8.	क्षेत्र के टूटे पाँच पुलों में वैली ब्रिज लगाए जाएं। इसे सैन बकारटा का पुल ग्रामीण विकास विभाग का है, अतः इस पुल को ग्रामीण विकास विभाग ही ठीक करे।	लोक निर्माण/ ग्रामीण विकास विभाग
9.	हर वर्ष बरसात में प्रभावित होने वाले एचआरटीसी धर्मपुर बस स्टैण्ड के प्रोटेक्शन वॉल कार्य को किया जाए।	लोक निर्माण विभाग/ बस अडडा प्राधिकरण

10.	विधानसभा क्षेत्र में दूध के कलैक्शन सेटंर और चिलिंग प्लांट लगाए जाए।	HP Milkfed/ पशु पालन विभाग
11.	आपदा के बाद सरकारी स्कूलों को हुए नुकसान को Disaster Mitigation के तहत पैसा देकर जल्दी ठीक किया जाए।	राजस्व विभाग/ शिक्षा विभाग (उच्चतर/स्कूल)
12.	जल शक्ति विभाग की 18 स्कीमें जिनका 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, शेष निर्माण कार्य को जल्दी पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
13.	सेरीकल्चर में प्रदेश सरकार New Policy बनाए तथा Cocoon में भी MSP दी जाए।	कृषि/उद्यान/पशु पालन/ उद्योग विभाग
14.	HPSHIVA प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार फसल के लिए उचित मूल्य दिया जाए तथा इस पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।	उद्यान विभाग
15.	कमलाह किला की Restoration की धनराशि को ट्रेजरी से जारी किया जाए।	भाषा कला एवं संस्कृति विभाग
16.	हल्दी के उत्पाद के लिए Cluster बनाया जाये तथा Marketing के लिए प्रयास किये जाएं।	कृषि / उद्योग विभाग
17.	नगर पंचायत धर्मपुर व संधोल में BPL तथा EWS के Certificate issue किये जाएं।	शहरी विकास विभाग
18.	बंजी-जंपिंग के ऊपर एक DPR बनाई है यह Tourism की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसे Priority पर रखें।	पर्यटन विभाग
	7. श्री अनिल शर्मा, मण्डी	
1.	विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत तैयार DPR जिसे NABARD को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है यदि ऐसी कोई भी DPR किसी अन्य मद जैसे PMGSY के तहत स्वीकृत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में NABARD को प्रेषित उस MLA Priority के विरूद्ध Substitution हो सके।	योजना विभाग
2.	PMGSY के अंतर्गत वही सड़कें ली जा सकती है Through Route (दो सड़कों को Connect करने वाली) नहीं होती है। PMGSY में ऐसी Condition होना राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ठीक नहीं है। अतः इस मुदद् को दिल्ली के स्तर पर उठाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	मंडी शहर को ट्रैफिक समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए NABARD में सड़कों की दो DPR तैयार की जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	एक Foot Bridge को Ambulance road बना दिया गया और Local MLA को इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए विधानसभा क्षेत्र में विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के समय योजनाओं के बारे में संबंन्धित क्षेत्र के विधायक को भी विश्वास में लिया जाए।	समस्त विभाग
5.	ताड़ा सड़क से एक लिंक सड़क के लिए Budget का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
6.	NABARD के अंतर्गत निर्मित सड़कों में जिनमें FCA violation हुआ है उसे State Exchequer को ही भुगतना है अतः जिसमें Penalties ज्यादा है उसे State Exchequer द्वारा दिया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	मंडी शहर के लिए सड़क की 6.50 करोड़ रूपये की एक DPR है उसकी Proposal को Centre Govt. को भेजा जाए।	लोक निर्माण विभाग
8.	मंडी कॉलेज के कैम्पस को तैयार करने के लिए मात्र रुपये 2.50 करोड़ की आवश्यकता है अतः इस राशि को दिया जाए।	शिक्षा विभाग(उच्चतर)
9.	पड्डल मैदान में एक टायलेट की सुविधा के लिए रुपये 01 करोड़ दिया जाए।	युवा खेल सेवाएं विभाग / उपायुक्त मण्डी
10.	पड्डल में Indoor Sports Stadium बनाने के लिए प्रयास किए जाएं।	युवा खेल सेवाएं विभाग
11.	मंडी में नई जेल के निर्माण कार्य को जल्दी पूरा किया जाए।	पुलिस विभाग
12.	मंडी शहर के लिए NGT Guidelines के बारे में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। वर्तमान Guidelines की वजह से बहुत सारे कार्य अवरुद्ध हैं।	शहरी विकास विभाग
13.	मंडी में Animal Husbandry की Building को पूरा करने के लिए मु0 1.25 करोड़ की आवश्यकता है अतः इस धनराशि को दिया जाए।	पशु पालन विभाग

14.	कोटली कॉलेज के भवन का सुधार किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
15.	Govt. Sr. Sec. School Kot का सुधार किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
16.	टारना Sinking क्षेत्र से Water Storage Tank को Shift करने बारे विचार करें।	जल शक्ति विभाग
17.	क्षेत्र में विद्यमान जल शक्ति विभाग के कार्यालयों में Staff दिया जाए।	जल शक्ति विभाग
18.	मंडी शहर में सड़क पर Paid Parking होने से आय बढ़ेगी और अवैध Parking भी रुकेगी।	शहरी विकास विभाग
19.	मंडी शहरी निकाय में Merger area के लिए भी अलग से Budget का प्रावधान करें और स्टॉफ दिया जाए।	शहरी विकास विभाग
20.	190 मेगावाट का थानापलौं Power Project का अब Rehabilitation तथा Resettlement का काम होना है अतः इसके लिए Budget प्रदान किया जाए।	HPPCLtd.
21.	कोटली क्षेत्र की 12 पंचायतों में Power Supply सुचारु रुप से चलाने के लिए इस क्षेत्र के 132/33 केवी के Feeder को धर्मपुर से जोड़ा जाए।	HPSEBLtd.
22.	Shiv Dham Tourism का Second Phase का काम भी शुरु करें।	पर्यटन विभाग
23.	मंडी Medical College में Radiologist की कमी को पूरा किया जाए।	स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा विभाग
	8. श्री ईन्द्र सिंह, बल्ह	
1.	मण्डी–गागल–चैलचौक–जंजैहली–छतरी–राणा सड़क है, मण्डी तथा गागल को इससे वंचित रखा गया है, इसमें 8–9 कि0मी0 क्षेत्र को भी जोड़कर टू–लेन कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2.	स्याहल–चण्डयाल तथा पैड़ी पस्ता पुलों के अधूरे निर्माण कार्य तथा एपरोचिज़ के कार्य को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए तथा कार्य पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	क्वाड़ मार्केट से ढांगू–सतसंग घर–गौशाला सड़क जो आपदा में खराब हुई है को बजट का प्रावधान कर ठीक किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	नगर परिषद ढांगू क्षेत्र में स्व0 ढोली राम के घर के आस–पास प्रोटेक्शन वॉल लगाई जाए तथा यहॉं पड़ने वाले नाले का तटीयकरण किया जाए।	शहरी विकास/जल शक्ति/लो0नि0 विभाग
5.	बस अडडा रिवॉलसर का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
6.	पी.एच.सी. सिधयाणी (20 प्रतिशत शेष कार्य) तथा लोहारा के भवनों के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए तथा कार्य पूर्ण किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
7.	वैटनरी अस्पताल भंगरोटू के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए तथा कार्य पूर्ण किया जाए।	पशु पालन विभाग
8.	साईंस लैब पैड़ी के अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही मैहरामसित पाठशाला में साईंस लैब खोली जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
9.	रा0व0मा0पा0 भंगरोटू (Girls) में साईंस लैब खोली जाए क्योंकि बेटियों को साईंस लैब के लिए Boys स्कूल में जाना पड़ता है, रास्ते में उनके साथ छेडछाड़ होती है। इसलिए भंगरोटू (Girls) स्कूल में प्राथमिकता के आधार पर खोली जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
10.	बल्ह क्षेत्र की 15 नं0 पंचायतों के लिए पीने के पानी की स्कीम में छूटी 7–8 पंचायतों को को पेयजल की सुविधा प्रदान की जाए।	जल शक्ति विभाग
11.	उठाऊ पेयजल योजना करनेहड़ा, कलसेहड़ा जो नाबार्ड में स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं को स्वीकृत करवाया जाए ताकि पुरानी पम्पिंग मशीनरी/ मोटरों / अन्य उपकरणों को बदलकर नये की स्थापना की जा सके।	जल शक्ति विभाग
12.	बैहना से नलसर वाया गागल सड़क को टू–लेन करने का कार्य जल्द से शुरु किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
13.	खियूरी–बंगलोह–राजगढ़ सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु बजट का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
14.	सकरोहा–नैना माता सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु बजट का प्रावधान किया जाए ताकि इस कार्य को पूरा किया जा सके।	लोक निर्माण विभाग

15.	नगर परिषद नेरचौक से डडौर तक सड़क के दोनों ओर पक्की नालियों का निर्माण करने के लिए लगभग 2 करोड़ रू0 का बजट का प्रावधान किया जाए तथा रत्ती से भंगरोटू तक भी सड़क के दोनों ओर पक्की नालियों का निर्माण करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	शहरी विकास / लोक निर्माण विभाग
16.	भियूरा–स्टोह–दौहल, भंगरोटू–नौरू, भंगरोटू–चौगान–छित्तर का गोहर, अरठी–बालासुन्दरी मन्दिर–हरिजन बस्ती रिहड़ी मंगलाह वाया मानपुर लखदाता मन्दिर मुड़ापर चौका माता मंदिर सड़क(कुल ल0 7 कि0मी0), चक्कर मोड़ से गड़सौल पाठर, गुट्कर से शिव गुफा, भड़याल से मलवाणा, चण्डयाल से काण्ढी तारापुर, बैहना–टिक्कर–बाड़ाधार–सुरनी नाला–मनसा माता खारसी–काण्ढी तारापुर, चण्डयाल–सिंहन–बह–कोहाल घटटा, रत्ती ढांगू, सड़कों जोकि गत बरसात में क्षतिग्रस्त हुई है के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
17.	टांवां–कुम्मी सड़क का लगभग 200 मीटर का भाग जोकि कच्चा रह गया है को पक्का करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
18.	खेल मैदान कन्सा की सुरक्षा के लिए क्रेटवॉल / सुरक्षा दीवार हेतु बजट का प्रावधान किया जाए।	युवा एवं खेल सेवाएं विभाग
19.	बरसात में क्षतिग्रस्त अन्य सड़कों के लिए भी बजट का प्रावधान किया जाए, जैसेः जीरो प्वाईट हनुमान मंदिर से बटाहण, गम्भर पुल से पतरौण–कोठी गैहरी, पतरौण हनुमान मंदिर से कोठी सरध्वार दुर्गापुर, खान्धी मोड़ से छ्ज्जवाण खाबू, मंज्याहली से सुक्का रियूर कोट, धार से चहड़ी बड़ाणू सिध्याणी, सिध्याणी पाथा धार रिवालसर, सिध्याणी से लोअर भावत गमौल गलू बरस्वाण, कपाही से झोर ट्रवाई, ट्रवाई से बरालणु घरभासड़ा लेदा, कठ्यांहूं से धार हल्यातर बुराहली, चहड़ी धार मुरारी माता, रिवालसर गलू से सरकीधार–नैणा माता, सरकीधार चौक से रा0उ0पा0 सरकीधार, रिवालसर गुदाहण डोह सरकीधार, पैड़ी पस्ता हवाणू गजनोहा, रत्ती ट्रोह पिपली गजनोहा तथा घौड़ चलहर–करनेहड़ गददीधार–कुपगलू–दुर्गापुर इत्यादि।	लोक निर्माण विभाग
20.	मुख्यमंत्री लोकभवन लेदा के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए बजट लगभग 30 लाख का प्रावधान किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
21.	बल्ह घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना (Right Bank) जोन नं0–1 की मुख्य नहर जोकि बग्गी से गॉव मलोरी तक लगभग 18 कि0मी0 लम्बी है, इसको पाईप लाईन में परिवर्तित करने की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि यह नहर सन 1994 में बनी थी तथा वर्तमान में जगह–जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिसके कारण इससे भारी रिसाव हो रहा है तथा अंतिम बिन्दु तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच रहा है। अतः विनम्र निवेदन है कि इस कार्य को विधिवत घोषणा करके टोकन बजट का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
22.	बल्ह घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना (Left Bank) मैरामसीत–बाल्ट–गलमा–मल्थेहड़–नेर–माण्डल परियोजना आपदा के कारण विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है, के नुकसान की भरपाई हेतु बजट का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
23.	बल्ह विधानसभा के अन्तर्गत ढांगू कूहल जोकि जगह–जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिससे किसानों को फसलों की सिंचाई हेतु भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस कूहल की मुरम्मत हेतु आवश्यक बजट का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
24.	बल्ह विधान सभा के अन्तर्गत रा0व0मा0पा0 गलमा, बरस्वाण, सिध्याणी, दसेहड़ा व हल्यातर के स्कूल भवन निर्माण हेतु बजट का प्रावधान किया जाए ताकि इन पाठशालाओं में भवनों के निर्माण कार्य किये जा सकें।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
25.	रा0उ0पा0 रियूर व राजकीय पाठशाला सरकीधार के भवन निर्माण कार्य हेतु बजट का प्रावधान किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
26.	निर्माणाधीन रा0उ0पा0 सकरोहा को पूरा करने के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
27.	रा0उ0पा0 बैहना के भवन निर्माण कार्य हेतु बजट का प्रावधान किया जाए। क्योंकि यहॉं भवन न होने के कारण बच्चों को अभी भी निजी भवन में पढ़ाया जा रहा है।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)

28.	आई.टी.आई गागल (बल्ह) का निर्माण कार्य जोकि अधर में लटका हुआ है इसके निर्माण को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
29.	अटल मैडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक को बल्ह विधानसभा में ही स्थापित किया जाए।	चिकित्सा शिक्षा विभाग
30.	मैडिकल कॉलेज नेरचौक तथा अन्य विभागों में कार्यरत आउटसोर्स के माध्यम से रखे कर्मचारियों को बरखास्त किया गया है। इनमें बहुत से कर्मचारी अपंग, विधवा तथा असहाय हैं। अतः इन कर्मचारियों को वरियता के आधार पर पुनः नियुक्त किया जाए।	चिकित्सा शिक्षा / समस्त सम्बन्धित विभाग
31.	मैडिकल कॉलेज नेरचौक में ट्रेनिंग सेन्टर के भवन के निर्माण हेतु बजट का प्रावधान हो चुका है। अतः इसका शिलान्यास शीघ्र किया जाए।	चिकित्सा शिक्षा विभाग
32.	सी.एच.सी. गागल के भवन निर्माण कार्य हेतु बजट का प्रावधान किया जाए।	चिकित्सा शिक्षा विभाग
33.	ग्राम पंचायत नटनेड़ तथा दरव्यास के भवन निर्माण हेतु बजट का प्रावधान किया जाए।	पंचायती राज विभाग
34.	डिनोटिफाई विद्युत विभाग मण्डल कार्यालय नेरचौक को नोटिफाई किया जाए।	HPSEBLtd.
35.	पुलिस थाना रिवालसर भी डिनोटिफाई हुआ है इसे भी नोटिफाई किया जाए।	पुलिस विभाग
36.	दुर्गापुर में वैटनरी अस्पताल तथा ग्राम पंचायत स्योहली में वैटनरी डिस्पैंसरी को भी पुनः नोटिफाई किया जाए।	पशु पालन विभाग
37.	आई.टी.आई. रिवालसर को भी डिनोटिफाई किया गया है इसे भी नोटिफाई किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
	9. श्री दलीप ठाकुर, सरकाघाट	
1.	Civil Hospital सरकाघाट के भवन में finishing के कार्य को पूरा कर इसे चालू किया जाए तथा यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
2.	CHC बलद्वाड़ा तथा जमणी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
3.	JJM के अंतर्गत निर्माणाधीन संधोल से सरकाघाट–सुरांगा तथा हटली पेयजल योजना का 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है, शेष 20 प्रतिशत कार्य करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाई ताकि निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके।	जल शक्ति विभाग
4.	सरकाघाट में पानी की पाईपों की कमी को दूर किया जाए।	जल शक्ति विभाग
5.	सरकाघाट बस डिपों में जीरो वैल्यू की 15 बसों के स्थान पर नई बसें दी जाएं। साथ ही ड्राईवरों की कमी को दूर किया जाए।	परिवहन विभाग/ HRTC
6.	सरकाघाट में मेडिकल कॉलेज तथा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोला जाए।	चिकित्सा शिक्षा / स्वास्थ्य विभाग
7.	क्षेत्र की सड़क त्रिफालघाट–बडौण–बठेड़ा–ठाणाचौकी–मुरारी देवी की दयनीय स्थिति को सुधारा / सुदृढ़ीकरण किया जाए, विशेषकर 3 कि0मी0 कच्ची सड़क को पक्का किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8.	ढलवाण–कोलणी–गैहरा–पनयाली–चन्देश–संसोह–मसेरन–सरकाघाट सड़क बरसात में खराब हो चुकी है। इस सड़क की मैटलिंग टारिंग / उचित मुरम्मत व रख–रखाव किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
9.	क्षेत्र की तीन रा0व0मा0पाठशालाओं चौक, मजयाठ तथा चौक बराथा में बच्चों के बैठने के लिए कमरों की उचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ–साथ नये भवनों का निर्माण किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
10.	सरकाघाट में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की प्रस्तावना को अमलीजामा पहनाया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
11.	भदरोता में पुलिस चौकी खोली जाए।	पुलिस विभाग
	10. जिला शिमला	
	1. श्री बलबीर सिंह वर्मा, चौपाल	
1.	केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत योजनाओं की जानकारी चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रदान की जानी चाहिए।	समस्त विभाग

2.	मनरेगा के अन्तर्गत चौपाल विधानसभा क्षेत्र में किस–किस पंचायत में कितनी–कितनी राशि का क्या–क्या कार्य किया गया है इसकी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
3.	जे.जे.एम. व अन्य माध्यम से जितनी भी योजनाएं 2004 के बाद भी जिनमें काम पूरा नहीं हुआ है और बिजली के ट्रांसफॉर्मर कार्य लटके हुए हैं या चालू नहीं है उसकी जाँच करवाई जाए।	जल शक्ति विभाग
4.	क्षेत्र की मुख्य सड़क सेंज–देहा–चौपाल–पीड़जपुल के सुधारीकरण का कार्य किया जाए। इस कार्य के सुधारीकरण के कार्य को दो भागों में किया जाए। पहले भाग में पराला से देहा तक तथा दूसरे भाग में चौपाल से देहा तक, यदि इसमें कोई FCA होना है तो उपायुक्त शिमला इस बारे समय पर उचित कार्रवाई करे।	लोक निर्माण विभाग/ उपायुक्त शिमला
5.	PMGSY में Gift Deed के issue को Bank के स्तर पर उठाकर दूर किया जाए।	सहकारिता विभाग
6.	निर्वाचन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों में जे.ई. के रिक्त पदों को भरा जाए तथा स्टाफ की कमी को दूर किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	क्षेत्र में 66 के.वी. पॉवर सप्लाई 30 कि0मी0 घने जंगल से होकर गुजरती है, जिससे लो–वोल्टेज की समस्या होती है इसे हल करने के लिए कुछ टॉवर व तारें बदली जानी हैं, ट्रॉंसफार्मर लगने है इत्यादि कार्य होना है, इन्हें जल्द पूरा किया जाए।	HPSEBLtd./ HPPTCLtd.
8.	शिलाई से नेरवा के लिए 66 के.वी. पॉवर सप्लाई दिये जाने बारे विभाग कार्रवाई करे।	HPSEBLtd./ HPPTCLtd.
9.	चौपाल क्षेत्र में 100 से 500 किलोवॉट के सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए।	हिम ऊर्जा
10.	चौपाल क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्र में आई.टी.आई. को दोबारा खोला जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
11.	टौंस नदी से पेयजल / सिंचाई योजना की डी.पी.आर. केन्द्र सरकार को प्रेषित कर शीघ्र स्वीकृत करवाई जाए।	जल शक्ति विभाग
12.	नेरवा बस डिपो FCA मामला अन्तिम चरण पर है इसे शीघ्र पूरा किया जाए।	परिवहन/ वन विभाग
13.	HPMC के अधीन क्षेत्र में दवाईयों की कमी है इसे पूरा किया जाए।	उद्यान विभाग/ HPMC
14.	चौपाल कॉलेज निर्माण हेतु जो धनराशि / बजट प्रस्तावित/ स्वीकृत है, उसे अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, इसे वापिस किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
15.	विधायक क्षेत्र विकास निधि को जारी किया जाए।	योजना विभाग
	2. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, रोहड़ू	
1.	सेब के बगीचों में बीमारियों के प्रबन्धन के लिए उपलब्ध दवाईयों में कमी आई है, इस कमी को जल्दी दूर किया जाए।	उद्यान विभाग
2.	क्षेत्र में स्थापित Milk Chilling Plant की बढ़ाई हुई capacity के कार्य को जल्दी पूरा किया जाए।	HP Milkfed
3.	सीमा महाविद्यालय में बी. एड. की कक्षाएं चलाने की अधिसूचना जारी की जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
4.	सीमा महाविद्यालय में छात्रावास (**Girls Hostel**) के कार्य को जल्दी पूरा किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
5.	निर्वाचन क्षेत्र में डे–बोर्डिंग स्कूल का निर्माण किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
6.	एम.डी.आर. 64 सड़क को रोहड़ू से टिक्करी तक 21 कि0मी0 के कार्य को गुणवत्ता के साथ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	जल शक्ति विभाग में 43 योजनाओं के कार्य 80 से 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके हैं। इन स्कीमों को 100 प्रतिशत पूरा करने के लिए धन उपलब्ध करवाया जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	PMGSY-Phase-II में डोडरा–क्वार सड़क के कार्य को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
9.	उतराखण्ड सरकार के साथ स्योह–दोगरी सड़क के मुद्दे को उठाकर इस सड़क के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग

10.	नागरिक अस्पताल रोहडू में नर्सो की कमी को दूर किया जाए।	स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा विभाग
11.	**Shiftiing & Upgradation of Sewerage Tank Rohru:** The existing facility be shifted to a suitable location and its capacity be enhanced to meet the present and future requirements. Further, sewerage connection may be provided to households not presently covered under the sewerage network to ensure proper sanitation and prevent contamination of the surrounding area.	Jal Shakti and Urban Development Deptt.
12.	**Laying of Sewerage Line in Nagar Panchayat, Chirgaons:** It is proposed that comprehensive sewerage line be laid in Nagar Panchayat, Chirgaon, so as to ensure safe disposal of wastewater, improve sanitation and environmental conditions, and cater to present and future requirements of the town.	Jal Shakti and Urban Development Deptt.
13.	**Providing LWSS to village Jaakhar, Kothal, Padanalla and its surrounding area:** it is requested that the concerned department may kindly take necessary steps to extend and strengthen the water supply scheme in this area at the earliest in the larger public interest.	Jal Shakti Deptt.
14.	**Providing LWSS to village Sharog and its surrounding area Tehsil Rohru Distt. Shimla HP :** it is requested that the concerned department may kindly take necessary steps to extend and strengthen the water supply scheme in this area at the earliest in the larger public interest.	Jal Shakti Deptt.
15.	**Pabber River Channelization from Tikkri to Hatkoti :** it is requested that the concerned department may kindly prepare the DPR and take necessary steps for channelization of the Pabber River from Tikkri to Hatkoti at the earliest in the larger public interest.	Jal Shakti Deptt.
16.	**C/o Bye-Pass road from Mehandli to Samoli :** it is requested that the concerned department may kindly conduct a feasiblility survey, prepare the DPR and accord administrative and financial approval for C/o this Bye-Pass at the earliest in the larger public interest.	Public Works Deptt.
17.	**C/o Bye-Pass road at Chirgaon :** it is requested that the concerned department may kindly take necessary steps for survey, prepare the DPR and accord administrative and financial approval for C/o this Bye-Pass at the earliest in the larger public interest.	Public Works Deptt.
18.	**Metalliing / Tarring of road from Andhra Project Chirgaon to Jabal Nallah (Length 9KM) :** it is requested that necessary budget provision may kindly be made and administrative approval accorded for M/T of the said 9 KM stretch at the earliest in the larger public interest.	Public Works Deptt.
19.	**Metalliing / Tarring of road from Chirgaon to Chilala (Length 4KM) :** it is requested that necessary budget provision may kindly be made and the work of M/T of road from Chirgaon to Chilala (4 KM) be taken up at the earliest in the larger public interest.	Public Works Deptt.
20.	**Installation / C/o bridge / Valley bridge over river Pubber from Chirgaon to Shishara :** it is requested that the concerned department may kindly conduct the necessary survey, prepare the DPR and accord administrative and financial approval for C/o this bridge over river Pubber at the earliest in the larger public interest.	Public Works Deptt.
21.	**Installation / C/o bridge over Sundru Khad at Janglikh :** it is requested that the concerned department may kindly conduct the necessary survey, prepare the DPR and accord administrative and financial approval for C/o this bridge at the earliest in the larger public interest.	Public Works Deptt.
22.	**Installation / C/o bridge/ Valley Bridge at Saribasa G.P Devidhar-Sari Khad :** it is requested that the concerned department may kindly conduct the feasibility survey, prepare the DPR and accord necessary administrative and financial approval for C/o this bridge at G.P Devidhar at the earliest in the larger public interest.	Public Works Deptt.
23.	**Installation / C/o Gumma bridge-Gumma, G.P Tikkeri :** it is requested that the concerned department may kindly undertake the necessary survey, prepare the DPR	Public Works Deptt.

	and accord administrative as well as financial approval for C/o this bridge at the earliest in the larger public interest.	
24.	**Installation / C/o Chirgaon bridge :** it is requested that the concerned department may kindly conduct a feasibility study, prepare the DPR and accord necessary administrative and financial approval for C/o this bridge at the earliest in the larger public interest.	Public Works Deptt.
25.	**Upgradation of MDR-64 road from Rohru to Tikkari (0/00 to 21/200KM) :** it is requested that necessary steps may kindly be taken to expedite the upgradation and strengthening of this road under the World Bank Assisted Scheme sat the earliest in the larger public interest.	Public Works Deptt.
26.	**Development of Tourism Areas in Rohru constituency as under:** Chanshal Pass, Kalka Patan, Moral Danda, Sungri and Rupin Pass and Chander Nahan by providing necessary infrastructure such as improved approach roads, parking facilities, wayside amenities, public conveniences, proper signage, viewpoints, trekking routes, eco-tourism facilities, safety measures and suitable arrangements. In view of the above it is requested that the concerned department may kindly prepare a comprehensive and phased tourism development plan for Rohru constituency and provide necessary budget allocation for the systematic development of the above mentioned areas in the larger public interest.	Tourism Department
	3. श्री हरीश जनारथा, शिमला शहरी	
1.	शिमला शहरी निर्वाचन क्षेत्र की विधायक प्राथमिकताओं में निर्धारित प्रपत्र में बदलाव कर इसमें छोटी-2 सड़कों को प्रदान के लिए अधिक महत्व दिया जाए। साथ ही शिमला शहर के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए।	शहरी विकास / योजना विभाग
2.	शिमला शहर की पेयजल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
3.	शिमला शहर में सर्कुलर सड़क को चौड़ा करने के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	डक्टिंग के कार्य को जल्दी पूरा किया जाए।	नगर निगम शिमला
	11. जिला कांगड़ा	
	1. श्री रणबीर सिंह, नूरपुर	
1.	मातृ शिशु अस्पताल नूरपुर के शेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु लगभग 3 करोड़ रूपये की धनराशि जारी कर कार्य को तीव्रगति से पूरा किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके।	स्वास्थ्य विभाग
2.	नागरिक अस्पताल नूरपुर में डॉक्टरों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। विशेषतः सिटी स्कैन डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ तथा बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
3.	चौगान में शॉपिंग कॉम्पलैक्स में लगभग 80-90 दुकानें बनकर तैयार हैं तथा जसूर ब्लॉक में भी इसी तरह कई वर्षो से 29 दुकानें बनकर तैयार हैं। इन तैयार दुकानों को किराये पर दिया जाए जिससे प्रदेश को आय प्राप्त होगी।	ग्रामीण विकास / शहरी विकास विभाग
4.	कांगड़ा जिला के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पंजाब राज्य की सीमा के साथ लगती है, जिससे वहॉं पर अवैध खनन हो रहा है। इस अवैध खनन को रोकने के लिए पंजाब राज्य की सीमा के साथ लगते क्षेत्रों की Demarcation की जाए जिससे अवैध खनन पर रोक लगेगी और सरकार को राजस्व प्राप्त होगा।	उद्योग विभाग
	2. श्री मलेन्द्र राजन, इन्दौरा	
1.	राम गोपाल मंदिर डमटाल का पैसा एफडीआर के रूप में हाईकोर्ट में वर्षो से पड़ा है, जो कि करोड़ों में है, Highcourt में इसकी strong पैरवी करके इसको रिलीज करवाया जाए ताकि मंदिर की दिशा दशा सुधारी जा सकें।	भाषा कला एवं संस्कृति विभाग
2.	रामगोपाल मंदिर डंमटाल की भूमि पर खैरों के पेड़ों की नीलामी शीघ्र करवाई जाए।	भाषा कला एवं संस्कृति/ वन विभाग

3.	गन्ना उत्पादकों की मांग को ध्यान में रखते हुए व उनकी समस्याओं को देखते हुए प्रदेश में Sugar Policy बनाई जाए और गन्ना उत्पादकों को अन्य राज्यों की तर्ज पर Incentive दिया जाए। इन्दौरा विधानसभा क्षेत्र के मीलवां में कृषि विभाग की खाली पड़ी 40 हैक्टेयर भूमि पर Sugar Mill का निर्माण करवाया जाए।	कृषि / उद्योग विभाग
4.	नशा क्लीनिकों, व नशा निवारण केंद्रों को बन्द करने के लिए पंजाब व J&K की तर्ज पर प्रदेश में पॉलिसी बनाई जाए व इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे इन क्लीनिकों और केंद्रों को तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए।	पुलिस / स्वास्थ्य विभाग
5.	इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ के पानी से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति को लेकर मुआवजा राशि शीघ्र जारी की जाए। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाए और व्यास नदी व अन्य खड्डों के तटीयकरण के कार्य को शीघ्र करवाया जाए ताकि आने वाले समय में नुकसान से बचा जा सके।	जल शक्ति विभाग
6.	इंदौरा टाउन की सीवरेज की डीपीआर नाबार्ड को भेजी गई है इसे तुरंत स्वीकृति दिलवाई जाए।	जल शक्ति विभाग
7.	क्षेत्र में प्रस्तावित 100 नए हैंडपंपों के निर्माण कार्य को नाबार्ड से शीघ्र स्वीकृति दिलवाई जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	ढांगू भदरोआ वाया कनिष्क आश्रम व ढाँगू माजरा एयरपोर्ट रोड जो कि चक्की खड्ड में आई बाढ़ के कारण बह गए थे, उनकी तुरंत मरम्मत करवाने के लिए राशि स्वीकृत की जाए।	लोक निर्माण विभाग
9.	हमारा विधान सभा क्षेत्र एग्रीकल्चर में, हॉर्टीकल्चर में, इंडस्ट्री में, दूध में, सब्जी में, फल उत्पादन में जिला कांगड़ा में सबसे आगे है पर हमारे लोगों को Facilities कम हैं, सब्जी मंडी नहीं है, कोल्ड स्टोर नहीं है. इनका निर्माण करवाया जाए।	कृषि विभाग/ Agriculture Marketing Board
10.	Skill Development सेन्टर खोला जाए ताकि फैक्ट्रियों में जरूरत के हिसाब से युवाओं को रोजगार मिल सकें।	कौशल विकास निगम
11.	सिविल अस्पताल इंदौरा, जिसको आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा मिला है, व सिविल अस्पताल गंगथ में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए व अन्य सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध करवाई जाएँ। इसके साथ–साथ डॉक्टरों, स्टाफ को आवासीय सुविधा के लिए बजट उपलब्ध करवाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
12.	इन्दौरा विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करवाया जाए व जमीन ट्रांसफर संबंधी कार्य को शीघ्र करवाया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
13.	इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित इंडोर स्टेडियम कम ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य को शीघ्र करवाया जाए। बजट उपलब्ध करवाया जाए, इसकी लैंड ट्रांसफर हो चुकी है।	युवा खेल सेवाएं विभाग
14.	राजकीय औद्योगिक संस्थान गंगथ में 3 नए ट्रेडों को मंजूरी दी जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
15.	राजकीय महाविद्यालय इन्दौरा में P.G. कक्षाओं को स्वीकृति दी जाए व शीघ्र शुरू करवाई जाएं।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
16.	इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय उच्च पाठशालाओं व राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं के भवन निर्माण के लिए बजट मुहैया करवाया जाए और पी0 एम0 श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गंगथ, व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठाकुरद्वारा को CBSE की मान्यता दिलाई जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
17.	इंदौरा क्षेत्र में प्रस्तावित कोल्ड स्टोर का शीघ्र निर्माण करवाया जाए।	उद्यान विभाग
18.	नैशनल हाईवे Damtal, Ram Gopal Temple की भूमि पर प्रस्तावित पार्क का निर्माण शीघ्र करवाया जाए व टूरिस्ट होटल का निर्माण शीघ्र करवाया जाए और दोनों कार्यों के लिए बजट उपलब्ध करवाया जाए।	भाषा कला एवं संस्कृति / पर्यटन विभाग
19.	क्षेत्र में प्रस्तावित वेटनरी सब डिविजन, गोवर्धन यूनिट व अपग्रेडेशन ऑफ वेटनरी डिस्पेंसरी द्रग बख्शियां और गगवाल के कार्य शीघ्र करवाए जाएं।	पशु पालन विभाग
20.	अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए मीलवां–बरोटा सड़क दिन में, इंदौरा–काठगढ़ सड़क पूरी तरह से व छौंछ खडड पर कन्दरोड़ी पुल व काठगढ़ पुल पर पंजाब के चोर रास्तों को बंद किया गया है। अवैध खनन	उद्योग /खनन विभाग

	में जारी ब्लैकमेलिंग को, फर्जी पत्रकारिता व इनमें संलिप्त अखबारों की ब्लैकमेलिंग का कड़ा संज्ञान लेकर इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए।	
21.	क्षेत्र में प्रस्तावित इन्दौरा बडुखर–तलवाड़ा, अम्ब–ऊना–चंडीगढ़ रूट पर HRTC की बस शीघ्र चलाई जाए।	HRTC
22.	पठानकोट डिपो की 9 बसें 2025 में पूरी तरह Condemn हो गई हैं। 5 बसें 31 दिसंबर 2026 को 15 साल की उम्र पार कर जाएंगी, तब 110 में से 14 बसें चली जाएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए पठानकोट डिपो में नई बसें उपलब्ध करवाई जाएं। Long Route की नई बसें उपलब्ध करवाई जाएं, चाहे डीजल की चाहे इलेक्ट्रिकल।	HRTC
23.	इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों व पुलों की रिपेयर के लिए बजट उपलब्ध कराया जाए।	लोक निर्माण विभाग
24.	क्षेत्र में पहले की डिमांड पुलिस चेकपोस्ट भदरोआ में खोली जाए। ठाकुरद्वारा पुलिस चौकी, पुलिस थाना डमटाल के भवन निर्माण के कार्य को शीघ्र करवाया जाए। पुलिस चौकी गंगथ जो कि नूरपुर थाना के अधीन आती है, इसको इंदौरा थाना के अधीन लाया जाए।	पुलिस विभाग
25.	एसडीएम इंदौरा व एसडीपीओ इंदौरा के आवासीय भवनों का निर्माण करवाया जाए व बजट उपलब्ध करवाया जाए।	राजस्व / पुलिस विभाग
26.	Combined ऑफिस बिल्डिंग गंगथ सब–तहसील व Combined ऑफिस बिल्डिंग ठाकुरद्वारा सब–तहसील के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र करवाया जाए व बजट उपलब्ध कराया जाए।	राजस्व / ग्रामीण विकास विभाग
27.	मिनी सचिवालय इंदौरा में एडवोकेट चैंबर व कैंटीन का निर्माण कार्य करवाया जाए व बजट उपलब्ध करवाया जाए।	राजस्व विभाग
28.	Request for establishment and proper functioning of the Court of the Learned Additional District and Session Judge at Sub-Division Indora.	राजस्व विभाग
29.	शाह नहर का डिविजन कार्यालय बडूखर में शिफ्ट किया गया है परन्तु बाढ़ के कारण शाह नहर को काफी नुकसान हुआ है। उसके लिए बजट उपलब्ध करवाया जाए ताकि किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सकें।	जल शक्ति विभाग
30.	132 केवी सब स्टेशन कंदरोड़ी का आगुमेंटेशन किया जाए व इसको अपग्रेड किया जाए।	HPSEBLtd.
31.	Request to shift the administrative control of 132 KV Substation rest house Kandoori from 220 KV Electrical system division Jassure to electrical division HPSEBL Indora.	HPSEBLtd.
32.	A request has been made for shifting of administrative control of certain areas from electrical division. HPSEBL Fatehpur (Fatehpur, constituency) to electrical division, HPSEBL Indora (Indora constituency) इसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।	HPSEBLtd.
33.	Request to sanction scheme for strengthening and modernization of electricity supply system of Kandrori- Damtal-Lodhwan Industrial area under electrical subvision HPSEBL Damtal under ED Indora.	HPSEBLtd.
34.	Request to fill field technical staff posts under Electrical Division HPSEBL Indora.	HPSEBLtd.
35.	Upgradation of Jassur- Gangath -Indora road km 4/000 to 27/200.	लोक निर्माण विभाग
36.	Construction of link road from Thakurdwara to Paral road km 0/00 to 2/300 including one no bridge.	लोक निर्माण विभाग
37.	Upgradation of Bharwain Chintapurni Khatiar Damtal road (Portion Indora to Badukhar km 65/000 to 87/000.	लोक निर्माण विभाग
38.	Request to sanction new HPPWD Rest House building at Thakurdwara in Indora Constituency.	लोक निर्माण विभाग
39.	Construction of new Water supply scheme for Gram Panchayat Baleer, Sirat Chaloh. Tappa and Bhogarwan in Indora Constituency in Tehsil Indora District Kangra HP	जल शक्ति विभाग
40.	Request to sanction C/o new Rest House Building of JSV in Indora Constituency.	जल शक्ति विभाग
	3. श्री बिक्रम सिंह, जसवां–प्रागपुर	
1.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग

2.	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षो में कितनी सड़कों की FCA हुई है या नहीं हुई के कारणों सहित ब्यौरा दें।	लोक निर्माण / वन विभाग
3.	रक्कड़–शांतला सड़क की डी.पी.आर. को भारत सरकार के माध्यम से CRIF के अन्तर्गत स्वीकृत करवाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	क्षेत्र के लिए बनी सिंचाई योजना की डी.पी.आर. को भारत सरकार के माध्यम से PMKSY के अन्तर्गत स्वीकृत करवाया जाए।	जल शक्ति विभाग
5.	PWD, XEN कार्यालय कोटला वेहड़ के भवन निर्माण कार्य को शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
6.	शूल खडड के पास बनी कौशल विकास निगम की Building को उपयोग में लाया जाए या किसी अन्य विभाग को उसे सौंप कर उसमें युवाओं को ट्रेनिंग इत्यादि प्रदान की जाए।	कौशल विकास निगम
7.	राजकीय पालीटेक्निक कॉलेज जन्डौर में चपरासी / सफाई कर्मचारी के पद को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए तथा कॉलेज में चल रहे तकनीकी व गैर तकनीकी रिक्त पदों को भी भरा जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
8.	सलेटी आदर्श विद्यालय के निर्माण के लिए जिन लोगों द्वारा भूमि दान दी गई है उन लोगों को उनकी भूमि वापिस की जाए, यदि वहाँ इस विद्यालय का निर्माण नहीं हो रहा है।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
9.	क्षेत्र में बन रहे पॉली वैटनरी क्लीनिक कोटला–वेहड़ का कार्य 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य को पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाए और निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए।	पशु पालन विभाग
10.	औद्योगिक क्षेत्र चनौर में ट्रांसफॉर्मर लगाकर विद्युत व्यवस्था को ठीक किया जाए।	HPSEBLtd.
11.	विधायक क्षेत्र विकास निधि से स्वीकृत कार्यो के लिए धनराशि जारी की जाए।	योजना विभाग
12.	विधायक ऐच्छिक निधि स्वीकृत कार्यों के लिए धनराशि जारी की जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
	4. श्री संजय रतन, ज्वालामुखी	
1.	ज्वालामुखी एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थान है इसके दृष्टिगत यहां पर हैलीपोर्ट / हैलीपैड का निर्माण किया जाए।	पर्यटन विभाग
2.	क्षेत्र में पॉलटेकनिक कॉलेज या आई.टी.आई. खोली जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
3.	खुंडियां सिविल अस्पताल का 50 बिस्तरों वाला भवन निर्माण सभी सुविधाओं के साथ शीघ्र किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	ज्वालामुखी अस्पताल में बिजली तथा पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त वांछित धनराशि रू0 2 करोड़ उपलब्ध करवाई जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी की बाउंड्री वॉल के मामले को हल किया जाए और निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए।	पुलिस विभाग
6.	जंदराह से लगडू वाया माढ़ तथा कुमकर कसेटी पुलों के अधूरे कार्य को एचरोचिज़ रोड़ के साथ शीघ्र निर्मित किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	खुंडियां को जोड़ने वाली मुख्य तीन सड़कों बड़ौली–मझीण, ज्वालामुखी–टिहरी तथा गुम्मर–बग्गी जो बरसात में खराब हो चुकी हैं को special fund उपलब्ध करवाकर शीघ्र ठीक किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8.	खुडियां में फॉयर सब–स्टेशन खोला जाए।	अग्निशमन विभाग
9.	ऐसी योजनाएं जा नाबार्ड को स्वीकृति हेतु Pose की गई हैं तथा किसी अन्य मद से स्वीकृत हो जाती हैं ऐसी नाबार्ड को प्रेषित योजनाओं को withdraw करने पर प्रेषित धनराशि की सीमा राशि हमारी NABARD kitty में वापिस आ जानी चाहिए। साथ इन योजनाओं को substitute भी किया जाना चाहिए।	योजना विभाग
10.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
	5. श्री विपिन सिंह परमार, सुलह	
1.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
2.	बैरघटा से डुग–धनियारा पुल का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य पूर्ण करने के लिए उचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।	लोक निर्माण विभाग

3.	बैरघटा से घंडेरा पुल, लोक निर्माण मण्डल भवारना का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य पूर्ण करने के लिए उचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	क्षेत्र में विद्यमान पी.एच.सी का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य पूर्ण करने के लिए उचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	सिविल अस्पताल भवारना का भवन लगभग बनकर तैयार है इसके शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए 2.5 करोड़ रू0 की धनराशि जारी की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
6.	पॉलटेकनिक कॉलेज सुलह ऐट परौर का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य पूर्ण करने के लिए उचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
7.	आई.टी.आई रझूं का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य पूर्ण करने के लिए उचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
8.	फॉर्मेसी कॉलेज स्वीकृत हुआ है जिसके लिए लगभग 80 कनाल भूमि का भी चयन कर लिया गया है, इसका निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
9.	राय दी कूहल, जल शक्ति मण्डल थुरल का मुरम्मत कार्य / रख–रखाव किया जाए।	जल शक्ति विभाग
10.	कृपाल चन्द कूहल (लगभग 38 कि0मी0 लम्बी) का मुरम्मत कार्य / रख–रखाव किया जाए।	जल शक्ति विभाग
11.	अत्याधिक खनन के चलते ठम्बु–कंगैण पेयजल योजना के नुकसान को ठीक किया जाए तथा यहॉँ पर खनन पर पूर्ण रोक लगाई जाए।	जल शक्ति / उद्योग/ खनन विभाग
12.	ऐच्छिक निधि से स्वीकृत योजनाओं की धनराशि जारी की जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
13.	किसान भवन भवारना रैस्ट हाउस का 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य पूर्ण करने के लिए उचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।	कृषि/उद्यान विभाग
	6. श्री पवन कुमार काजल, कांगड़ा	
1.	तकीपुर राजकीय महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों (अर्थशास्त्र, हिन्दी, संगीत इत्यादि) के रिक्त पदों को भरा जाए साथ ही तकनीकी पद जैसे कर्लक, लैब अटैण्डेन्ट इत्यादि।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
2.	राजकीय महाविद्यालय मटौर का भवन तैयार है इसका उदघाटन कर इसे आरम्भ किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
3.	लोक निर्माण विभाग (12) तथा जल शक्ति विभाग (4) की डी.पी.आर. तैयार कर योजना विभाग को स्वीकृति के लिए भेजी गई हैं। इनमें से कुछ डी.पी.आरज़ नाबार्ड के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं तथा कुछ योजना विभाग के पास विचाराधीन हैं। इन लम्बित पड़ी डी.पी.आरज़ को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।	लोक निर्माण / जल शक्ति/ योजना विभाग
4.	डिनोटीफाई PHCs रानीताल, गालियां तथा राजल को पुनः नोटिफाई किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	टांडा मेडिकल कॉलेज की बन्द पड़ी Lifts का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यहॉँ पर पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
6.	अस्पताल के नजदीक सराय भवन (For Attendant) का निर्माण करवाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
7.	चैतड़ू से लेकर नीचे 5–6 गॉँव के लिए गरनांव कूहल की डी.पी.आर. को जल्द तैयार कर इसे स्वीकृत करवाया जाए और इसका सुचारू संचालन किया जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	नटेड़ पुल के लिए 1 करोड़ रू0 की धनराशि का प्रावधान कर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
9.	क्षेत्र के निर्माणाधीन (लगभग 80–90 प्रतिशत तक पूर्ण) सब हैल्थ सेन्टर तथा PHCs के शेष कार्यो के लिए उचित धन की व्यवस्था कर निर्माण कार्य पूर्ण किए जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
10.	लोकभवन का कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है, परन्तु ठेकेदार की मृत्यु के कारण आगे का कार्य रूका हुआ है, इसके शेष कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
	7. श्री आशीष बुटेल, पालमपुर	
1.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग

2.	धरेड़ गाँव तथा आरठ, लाहला और री गाँवों / क्षेत्र के लिए दो पेयजल योजनाओं निर्माण के लिए बजट (लगभग 6–7 करोड़ रू0) का उचित प्रावधान कर योजना का निर्माण शीघ्र आरम्भ / पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
3.	शहरी पेयजल योजना में लगभग 50 लाख रू0 की liability है इसे पूरा किया जाए ताकि आगे निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके।	जल शक्ति/ शहरी विकास विभाग
4.	नगर निगम में मर्ज एरिया में पानी के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, (लगभग 450 रू0) इन्हें पुरानी दरों पर ही जारी किया जाए।	जल शक्ति विभाग
5.	पर्यटन की दृष्टि से सौरभ वन विहार के Suspension Bridge (Foot Bridge) की मुरम्मत तथा रख–रखाव के लिए 50 लाख रू0 की धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।	लोक निर्माण विभाग
6.	क्षेत्र के लिए की गई मुख्यमंत्री घोषणा के दो पुलों मणिमहेश तथा लशयाड़ु का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	पालमपुर के लिए बन रहे दो ROBs को भारत सरकार के माध्यम से बनाना है इनके निर्माण कार्यों को आरम्भ करने के लिए प्रदेश सरकार धन की कुछ व्यवस्था करने की कृपा करे।	लोक निर्माण / परिवहन (रेलवे) विभाग
8.	पालमपुर में सर्किट हाउस तैयार है इसे चालू किया जाए।	सम्बन्धित विभाग
9.	शिक्षा विभाग द्वारा बनाई जा रही library को पूर्ण करने के लिए 40–50 लाख रू0 की धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
10.	पालमपुर अस्पताल में MRI की मशीन पी.पी.पी. मोड पर लगाई जाए। इसके साथ–साथ यहाँ स्टाफ नर्सों, एनेस्थीसिया, आर्थो और त्वचा विज्ञान के चिकित्सकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
11.	सी.एच.सी. गोपालपुर में स्टाफ नर्सों तथा चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
12.	ईन्डोर स्टेडियम का निर्माण कार्य 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है शेष कार्य पूर्ण करने के लिए धन का प्रावधान किया जाए।	युवा खेल सेवाएं विभाग
13.	क्षेत्र के लोगों को मकान बनाने के लिए 2–2 किश्तें मिल चुकी हैं तथा अगली किश्तें कुछ नियम शर्तों के कारण नहीं मिल रही हैं इस बारे विभाग कार्रवाई करे।	पंचायती राज विभाग
14.	शहरी क्षेत्रों में MMSAGY (मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना) योजना चलाई जाए।	शहरी विकास विभाग
15.	पालमपुर में वैलनेस सेन्टर खोला जाए।	स्वास्थ्य विभाग
	8. श्री किशोरी लाल, बैजनाथ	
1.	उतराला–होली सड़क तृतीय चरण के कार्य को शीघ्र किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2.	बैजनाथ सिविल अस्पताल को 150 बिस्तर किया जाए तथा पूरे स्टाफ का प्रबन्ध किया जाए साथ ही आर्थो तथा गाईनी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
3.	चढ़ियार अस्पताल में भी नर्सों के रिक्त पदों को भरा जाए और मेडिसीन के चिकित्सक की नियुक्ति की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	बैजनाथ एच.आर.टी.सी. डिपों में नई बसें लगाई जाए।	HRTC
5.	जल शक्ति मण्डल बैजनाथ को धन उपलब्ध करवाया जाए।	जल शक्ति विभाग
6.	पॉलटेकनिक कॉलेज बैजनाथ (मुख्यमंत्री घोषणा) के निर्माण कार्य को आरम्भ किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
7.	पपरोला–रक्कड़ सड़क की दयनीय स्थिति को ठीक किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8.	शिव मंदिर बैजनाथ के साथ भूमि कटाव (land slide) होता है इस समस्या का समाधान किया जाए।	लोक निर्माण/भाषा कला एवं संस्कृति विभाग
	9. श्री आर. एस. बाली, नगरोटा बगवां	
1.	ब्लॉक सामुदायिक केन्द्र बड़ोह के निर्माण बारे।	ग्रामीण विकास विभाग
2.	अग्निशमन केन्द्र बड़ोह का निर्माण / स्थापित करने बारे।	अग्निशमन विभाग
3.	आधुनिक पुलिस स्टेशन नगरोटा बगवां का निर्माण / स्थापित करने बारे।	पुलिस विभाग
4.	सब जज कोर्ट नगरोटा बगवां खोलने बारे।	राजस्व विभाग

5.	वृद्धा आश्रम नगरोटा बगवां का निर्माण / स्थापित करने बारे।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
6.	समलोटी–सरोत्री सड़क का उन्नयन कि0मी0 0/0 से 4/0 तक, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा।	लोक निर्माण विभाग
7.	ग्राम पंचायत धलूं में बहाव सिंचाई योजना चकलू कूहल का निर्माण।	जल शक्ति विभाग
8.	लूहना–मंगरेला के लिए उठाऊ पेयजल योजना प्रदान करना।	जल शक्ति विभाग
9.	राजकीय उच्च विद्यालय, कलेड़ में दो अतिरिक्त कमरे, बरामदा व सीढ़ियों का निर्माण।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/स्कूल)
10.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसौर में दो अतिरिक्त कमरों का निर्माण।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/स्कूल)
11.	हरिजन बस्ती थान और साथ लगते गांवों के लिए उठाऊ पेयजल योजना का सुधार।	जल शक्ति विभाग
12.	हरिजन बस्ती देहरू–गरहैतड–हरयात और साथ लगते गांवों के लिए उठाऊ पेयजल योजना का सुधार।	जल शक्ति विभाग

माननीय मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव

दो दिवसीय बैठकों के अन्त में मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि इन दो दिवसीय बैठकों में 68 विधायकों में से 60 माननीय विधायकों ने भाग लिया । बैठकों में प्रदेश महत्व के विभिन्न मुद्दे माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए हैं । कुछ मुद्दों पर बैठकों में ही निर्णय लिए गए हैं । अन्य मुद्दों पर विभाग तुरन्त कार्रवाई करेंगे तथा की गई कार्रवाई से सरकार को अवगत करवाएंगे। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास किया जाएगा तथा विकास में रही त्रुटियों को दूर किया जाएगा।

बैठकों के समापन पर मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश ने माननीय मुख्य मन्त्री, मन्त्रीगण, उपाध्यक्ष (राज्य योजना बोर्ड), उपाध्यक्ष (पर्यटन), उप–मुख्य सचेतक (हि0प्र0विधान सभा), विधायकों, समस्त प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी उपायुक्तों व उपस्थित अन्य अधिकारियों का दो दिवसीय बैठकों में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया तथा स्पष्ट किया कि दो दिवसीय बैठकों में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों का सभी विभागों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा । प्रदेश के चहुंमुखी तथा समाज के सभी वर्गों के त्वरित व सन्तुलित विकास के लिए, सम्पूर्ण प्रशासन, सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान करेगा । सभी सम्बन्धित विभाग बैठकों में लिए गए निर्णयों एवं माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई से माननीय विधायकों तथा योजना विभाग मुख्यालय को समयबद्ध सीमा में अवगत करेंगे। दो दिवसीय बैठकें धन्यवाद प्रस्ताव सहित सम्पन्न हुईं।

दो दिवसीय बैठकों में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश

दो दिवसीय बैठकों में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश		
क्र. सं.	माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के निर्देश	सम्बन्धित विभाग
1.	चिन्तपूर्णी विधान सभा के स्थोतर पुल का काम SCDP Component के तहत किया जा रहा है जो पूरा नहीं हुआ है। इस पुल के कार्य को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण / योजना विभाग
2.	लोहारली में लगभग 50 करोड़ रू0 की लागत से जो पुल बनकर तैयार है उसकी अपरोचिज़ में में आ रही भूमि पर कोर्ट द्वारा जिन नम्बरों पर स्टे लगा है उन्हें छोड़कर दूसरे नम्बरों से कार्य को किया जाए और अभी के लिए फिल्हाल सिंगल लाईन शुरू किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	लोगों द्वारा Fecal Sludge को टैंकरस के द्वारा नदी नालों में बहाया जा रहा है। इसे रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांटस लगाने की आवश्यकता है, ताकि लोग उस Fecal Sludge को ट्रीटमेंट प्लांटस में ही डाल सकें। इस बारे बजट का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति / योजना विभाग
4.	निर्वाचन क्षेत्र गगरेट की पी.एच.सी. अमलेहड़ में महिला विशेषज्ञ चिकित्सक के पद को भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	योजना विभाग सभी माननीय विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र की विधायक प्राथमिकताओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी तीन महीने में उपलब्ध करवाए और योजनाओं के विषय में माननीय विधायकों से चर्चा भी करे।	योजना विभाग
6.	पी.जी.आई. सैटेलाईट सैन्टर ऊना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए 3 करोड़ रू0 की धनराशि बजट 2026-27 में दे दी जाए।	जल शक्ति/ योजना विभाग
7.	पी.जी.आई. सैटेलाईट सैन्टर ऊना चालू होने के बाद चिकित्सकों और पैरा मैडिकल स्टाफ की भर्ती की जाए / rationalize किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
8.	धनेत पुल की डी.पी.आर. शीघ्र तैयार की जाए।	लोक निर्माण विभाग
9.	लोक निर्माण विभाग स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर भवनों के नक्शों का निर्माण / प्लान करे।	लोक निर्माण विभाग
10.	बंगाणा तथा थानाकलां अस्पतालों के भवनों को तैयार करने के लिए लगभग 2-2 करोड़ रू0 की आवश्यकता है, इसे जारी किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
11.	यदि किसी भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है तो लोक निर्माण विभाग उस भवन को सम्बन्धित विभाग को सौंप दे और यदि कोई liability शेष है तो विभाग उसे बाद में भी चुका दे।	समस्त सम्बन्धित/ लोक निर्माण विभाग
12.	निर्वाचन क्षेत्र भोरंज की सिंचाई तथ पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए सोलर सिस्टम प्लांट लगाने की possibility देखी जाए।	हिम ऊर्जा / जल शक्ति विभाग
13.	निर्वाचन क्षेत्र भोरंज की लदरौर-पटटा पेयजल योजना की डी.पी.आर. को स्वीकृत करने बारे विभाग उचित कार्रवाई करे।	जल शक्ति / योजना विभाग
14.	प्रदेश की पेयजल योजनाओं में ओजोनेशन तकनीक को लागू किया जाए।	जल शक्ति विभाग
15.	प्रदेश में चिकित्सकों की ऑनलाईन हाजिरी लगाने के लिए अस्पतालों से एरियल डिस्टेंस 50 मीटर से कम कर 15-20 मीटर किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
16.	बड़सर विधान सभा में पड़ने वाले रैली जजरी स्कूल के जर्जर भवन को गिराकर नए भवन निर्माण के सम्बन्ध में जाँच कर कार्रवाई की जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
17.	नव गठित नगर पंचायत मैहरे तथा बड़सर में पड़ने वाले कृषि वाले क्षेत्र बणी, ठाणा, रैल, मकतेड़ी, तुखाणी इत्यादि को नगर पंचायत से बाहर किया जाए। इस बारे शहरी विकास विभाग उचित कार्रवाई करे।	शहरी विकास विभाग
18.	प्रमुख अभियन्ता जल शक्ति विभाग तथा सभी प्रशासनिक सचिव cleanliness of water and replacement of old pumping machinery का लगभग 1500 करोड़ रू0 की लागत का Quality Water Project बनाने बारे रिपोर्ट प्रस्तुत करे।	जल शक्ति विभाग

19.	पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के रा0व0मा0 पाठशाला हाब्बन के अधूरे भवन निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए धनराशि जारी की जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर/ स्कूल)
20.	मेडिकल कॉलेज नाहन में कार्डियोलॉजिस्ट का पद सृजित किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
21.	माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित भोगपुर–सिंबलवाला गाँव सड़क पर 6.58 करोड़ रू0 लागत से बनने वाले पुल का निर्माण अतिशीघ्र किया जाए।	लोक निर्माण / योजना विभाग
22.	प्रदेश में ट्रॉंसफॉर्मर लगाने के कार्य को तीव्रगति से अविलम्ब पूरा किया जाए। इसके साथ–साथ फिडोमीटर से लाईन में स्मार्ट मीटर तक सप्लाई सुनिश्चित की जाए। यदि कोई ठेकेदार समय पर काम न करे तो उन पर पैनल्टी लगाई जाए और उपकरणों / सामान (material) की कमी को दूर कर, गुणवत्तापूर्ण कार्य का विशेष ध्यान रखा जाए।	HPSEBLtd. / HPPTCLtd.
23.	सोलन–मीनस सड़क की डी.पी.आर. को अगले वर्ष CRIF में स्वीकृत करने के लिए भारत सरकार को प्रेषित किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
24.	रेणुका डैम प्रोजेक्ट के बनने से मुख्य सड़क संगड़ाह को बन्द कर किसी अन्य स्थान से बनाया जाना है जिससे 14 कि0मी0 की दूरी बढ़ रही है। इस सड़क के स्थान पर यहां पर एक सुरंग (1.5 से 2 कि0मी0) का निर्माण करने लिए हि0प्र0 पॉवर कॉरपोरेशन एक अध्ययन करे।	HPPCLtd.
25.	प्रदेश के जिन Single Teacher स्कूलों में से शिक्षकों को स्थानांतरित किया गया है उन्हें वापिस लाया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
26.	उपायुक्त सिरमौर विशेष रूप से निर्वाचन क्षेत्र पावंटा साहिब की माईनिंग क्षेत्र की सड़कों से होने वाली आय / रॉयल्टी की रिपोर्ट प्रस्तुत करे।	उपायुक्त सिरमौर
27.	सी.एच.सी. नालागढ़ स्थानांतरित की गई गाईनी चिकित्सक को वापिस नालागढ़ लाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
28.	पट्टा–खडली–जतरोग सड़क पर खडली पुल यदि विधायक प्राथमिकता में है तो इसे इसे जल्द स्वीकृत किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
29.	प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग बददी कॉरपोरेशन में internal circular road तथा बददी–बरोटीवाला सड़क के कार्य को फेज–I, II और III में करने बारे अध्ययन कर रिपोर्ट से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवाए।	लोक निर्माण विभाग
30.	लोक निर्माण विभाग डिवीजन बददी खोलने की फाईल को कैबिनेट में लाया जाए।	लोक निर्माण विभाग सचिव लोक निर्माण
31.	क्षेत्र की छोटी–छोटी ग्रामीण सड़कों (0.5 to 5 km approximately) के विस्तारीकरण / सुधारीकरण / सुदृढ़ीकरण की एक क्लब डी.पी.आर. (bunches of schemes) यदि बनाई जाए तो उसे नाबार्ड से स्वीकृत करवाने बारे विभाग कार्रवाई करे।	योजना विभाग
32.	कसौली क्षेत्र की गिरी नदी से उठाऊ पेयजल योजना के 7 पाईपें डालने के कार्य, लगभग 300 मीटर को उपायुक्त सोलन तथा पुलिस अधीक्षक सोलन, जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता के साथ मिल कर पूरा करे। ताकि योजना का लाभ जनता को प्रदान किया जाए।	उपायुक्त सोलन / जल शक्ति/ पुलिस विभाग
33.	सभी उपायुक्त, सभी विभागों के साथ प्रत्येक माह एक बैठक जरूर ले जिसमें उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यो की समीक्षा की जाए और यदि कोई समस्या आती है तो उसका त्वरित हल निकाला जा सके।	समस्त उपायुक्त
34.	चुराह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक प्राथमिकता योजनाओं की डी.पी.आर्ज़ को शीघ्र तैयार किया जाए।	जल शक्ति / लोक निर्माण/योजना विभाग
35.	चम्बा मेडिकल कॉलेज के 200+300 कुल 500 बिस्तर का निर्माण एक ही जगह सरोल में किया जाए। इसके साथ–साथ स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद के टैण्डर कार्य को पूरा किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
36.	प्रदेश में विद्यमान जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने बारे विभाग अध्ययन करे, इसमें विभिन्न श्रेणियों के पदों के merger करने का ध्यान भी रखा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
37.	प्रदेश में जिस भी जिला में जब कोई भी सरकारी कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया जाए तो उस जिले के	समस्त उपायुक्त

	उपायुक्त, उस जिला के माननीय विधायकों को एस.डी.एम. के माध्यम से कॉर्ड के माध्यम से स्वंय आमन्त्रित करेंगे।	
38.	कोलडैम रिजरवायर में स्पोर्टज़ एक्टीविटी (जलक्रीड़ाएं) चलाई जाएं साथ–साथ पर्यटन / पर्यटक गतिविधियों को आरम्भ किया जाए।	युवा खेल सेवाएं/ पर्वतारोहण खेल संस्थान/पर्यटन वि0
39.	बेसहारा पशुओं तथा जंगली जानवरों से किसानों तथा बागवानों की फसलों को बचाने के लिए 8 फुट वाली जालीदार तारों की बाड़बंदी का प्रावधान अगले बजट में किया जाए।	कृषि / पशु पालन विभाग
40.	अमरसिंहपुरा सड़क के लिए आधे बिस्वा भूमि का अधिग्रहण अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
41.	श्री नैना देवी जी निर्वाचन क्षेत्र की स्वाहन से कटीरड़–पंगवाना सड़क की डी.पी.आर. को नाबार्ड से शीघ्र स्वीकृत करवाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
42.	PMGSY-IV के तहत प्रदेश में आई सड़कों के लिए सभी जिला उपायुक्त non availability of non forest land प्रमाण पत्र व अन्य सभी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र एकमुश्त जारी करें, ताकि इन सड़कों की डी.पी. आर. को समय पर तैयार किया जा सके।	समास्त उपायुक्त
43.	नवगॉव–बैरी सड़क पर बागा क्षेत्र की 4–5 कि0मी0 सड़क के बचे कार्य को 19 करोड़ रू0 की बचत राशि से पूरा किया जाए तथा कार्य आरम्भ / पूर्ण करने से पहले माईनिंग विभाग के साथ पत्राचार किया जाए और जितना व्यय इस सड़क पर होता है उसे कम्पनी से क्लेम किया जाए।	लोक निर्माण / उद्योग / खनन विभाग
44.	जनहित को ध्यान में रखते हुए लोगों को उनकी भूमि से बिजली के खम्बे, तारें स्थानांतरित करने पर आने वाले व्यय को विधायक क्षेत्र विकास निधि से व्यय करने बारे विभाग कार्रवाई करे।	योजना विभाग / HPSEBLtd.
45.	पूरे प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास के लिए होटलों तथा होम स्टे के निर्माण हेतु Fire NOC and Bar License जारी करने की शर्तो तथा नियमों में छूट (provisional) प्रदान की जाए। विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में इस छूट को पूरी तरह से जारी किया जाए।	पर्यटन / अग्निशमन विभाग
46.	सी0एच0सी0 पतलीकुहल में चिकित्सक के पद को सृजित किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
47.	Tourism Dev. corporation का Mandate change करने की आवश्यकता है ताकि लोकल लेवल पर ही धन की उपलब्धता हो सके और छोटे–2 कार्यो का निष्पादन समय पर हो सके।	पर्यटन विभाग
48.	उपायुक्त कुल्लू Tourist Season के समय होम गॉर्ड जवानों की संख्या में बढ़ोतरी का प्रबन्ध करे, जिसका सारा खर्च Tourism Dev. Corporation के माध्यम से किया जाए।	उपायुक्त कुल्लू
49.	DGP होम गार्ड 200 जवानों को Tourist Season के समय उपायुक्त कुल्लू को सौंप दे ताकि उपायुक्त इन जवानों की डयूटी रोहतांग, मेन मनाली व अन्य आवश्यक स्थानों पर लगा सके।	गृह विभाग
50.	फोर लेनिंग के कार्य करते समय एचरोचिज़ सड़कों को जोड़ा / बनाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
51.	बढ़ते पर्यटन के दृष्टिगत नए स्थानों को चिन्हित किया जाए तथा गुणवत्तापूर्ण पर्यटन को सुनिश्चित किया जाए।	पर्यटन विभाग
52.	कुल्लु के होला मोहल्ला में लॉ एण्ड ऑर्डर को ठीक करने के लिए QRT लगाई जाए तथा इस टीम में कमाण्डो लगाए जाएं।	पुलिस विभाग
53.	पुलिस स्टेशन मणिकर्ण एट कसोल में पूरा स्टाफ प्रदान कर इसे चालू किया जाए।	पुलिस विभाग
54.	बंजार निर्वाचन क्षेत्र को चार–पांच भागों में बांटकर बिजली की समस्या का हल किया जाए।	HPSEBLtd.
55.	विद्युत विभाग में टैण्डर की प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता है। यदि RVNL टैण्डर हो जाने के बाद भी काम नहीं कर रहा है तो उनसे काम वापिस लेकर विद्युत विभाग स्वंय कार्य करे।	HPSEBLtd.
56.	बजौरा विद्युत सब–स्टेशन का सुदृढ़ीकरण किया जाए।	HPSEBLtd.

57.	लोक निर्माण विभाग में टैण्डर अवार्ड होने के बाद 10 दिन के भीतर कार्य आरम्भ हो जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में विभाग दिशा–निर्देशों से अवगत करवाए।	लोक निर्माण विभाग
58.	भुंतर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण के लिए लगभग 500 मीटर भूमि के चयन बारे उपायुक्त कुल्लू कार्य करे।	उपायुक्त कुल्लू / पर्यटन विभाग
59.	समेज खडड में आई बाढ़ से प्रभावित तीन परिवारों को 10 दिन के भीतर मुआवजा प्रदान किया जाए।	उपायुक्त कुल्लू
60.	आनी क्षेत्र के ब्रौं एरिया को रामपुर पुलिस डिवीजन के भीतर शामिल किया जाए।	पुलिस विभाग
61.	ITI करसोग के भवन को पूरा करने के लिए धनराशि जारी की जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
62.	सुन्दरनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक प्राथमिकता की नीरी से चरखड़ी सड़क की डी.पी.आर. को नाबार्ड से शीघ्र स्वीकृत करवाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
63.	सुन्दरनगर क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के निर्माणाधीन रैस्ट हाउस के 20 प्रतिशत शेष कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
64.	लोक निर्माण विश्राम गृह धनोटू का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है इसका उदघाटन कर इसे चालू किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
65.	रा0व0मा0 पाठशालाएं मौवीं सेरी तथा किलींग में साईंस लैब निर्माण हेतु टैण्डर लगाए जाएं तथा इनके निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर / स्कूल)
66.	मंडी–गागल–चेलचौक–जंजहैली सड़क के Rehabitation का कार्य जिसे CRIF के अंतर्गत मंजूरी मिली है उसमें बग्गी से चेलचौक तक सड़क का नाम भी जोड़ा जाए।	लोक निर्माण विभाग
67.	भारी बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए बचे हुए पात्र व्यक्तियों तक भी राहत राशि पहुंचाई जाए। एक व्यक्ति डूनेराम का मकान ध्वस्त हुआ है, उसे मात्र 70 हजार ही मिले हैं। शेष राशि का भुगतान अतिशीघ्र किया जाए।	राजस्व विभाग/ उपायुक्त मण्डी
68.	भारी बरसात की आपदा में जोगिन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र की कई गांव की सड़कें बंद है, इन्हें खोला जाए। वर्ष 2023 के बाद पक्की सडकों की टायरिगं नहीं हुई है, इसे भी करवाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
69.	जोगिन्द्रनगर विधानसभा का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होने के नाते इस क्षेत्र में सड़कों आदि के विकास के मामले में अलग योजना की आवश्यकता है। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से योजनाओं का युक्तिकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
70.	जल शक्ति विभाग की जोगिन्द्रनगर विधानसभा की बरसात के कारण प्रभावित योजनाओं को जल्दी ठीक कर पीने के पानी की समस्या का हल किया जाए।	जल शक्ति विभाग
71.	विधानसभा क्षेत्र जोगिन्द्रनगर में जल शक्ति विभाग की 90 प्रतिशत तक पूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने हेतु उचित बजट प्रदान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
72.	जोगिन्द्रनगर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की बहुत समस्या को जल्दी ठीक किया जाए।	HPSEBLtd.
73.	विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में दूध के कलैक्शन सेटंर और चिलिंग प्लांट लगाए जाए तथा इन्हें private sector में भी देने बारे विचार किया जाए।	HP Milkfed/ पशु पालन विभाग
74.	HPSHIVA प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार फसल के लिए उचित मूल्य दिया जाए तथा इस पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।	उद्यान विभाग
75.	हल्दी के उत्पाद के लिए Cluster बनाया जाये तथा Marketing के लिए प्रयास किये जाए।	कृषि / उद्योग विभाग
76.	निर्वाचन क्षेत्र धर्मपुर की नगर पंचायत धर्मपुर व संधोल में BPL तथा EWS के Certificate issue किये जाएं।	शहरी विकास विभाग
77.	धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र की बंजी–जंपिंग के ऊपर एक DPR बनाई है यह Tourism की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसे Priority पर रखें।	पर्यटन विभाग

78.	मण्डी–गागल–चैलचौक–जंजैहली–छतरी–राणा सड़क है, मण्डी तथा गागल को इससे वंछित रखा गया है, इसमें 8–9 कि0मी0 क्षेत्र को भी जोड़कर टू–लेन कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
79.	पी.एच.सी. सिधयाणी (20 प्रतिशत शेष कार्य) के अधूरे भवन निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए तथा कार्य पूर्ण किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
80.	विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत तैयार DPR जिसे NABARD को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है यदि ऐसी कोई भी DPR किसी अन्य मद जैसे PMGSY के तहत स्वीकृत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में NABARD को प्रेषित उस MLA Priority के विरूद्ध Substitution हो सके।	योजना विभाग
81.	मंडी शहर के लिए सड़क की 6.50 करोड़ की एक DPR है उसकी Proposal को Centre Govt. को भेजा जाए।	लोक निर्माण विभाग
82.	मंडी कॉलेज के कैम्पस को तैयार करने के लिए रु 2.50 करोड की राशि को दिया जाए।	शिक्षा विभाग(उच्चतर)
83.	मंडी निर्वाचन क्षेत्र में कोटली क्षेत्र की 12 पंचायतों में Power Supply सुचारु रुप से चलाने के लिए इस क्षेत्र के 132/33 केवी के Feeder को धर्मपुर से जोड़ा जाए।	HPSEBLtd.
84.	विधायक निधि से पानी की पाईपें खरीदने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं।	योजना विभाग
85.	सरकाघाट क्षेत्र की सड़क त्रिफालघाट–बडौण–बठेड़ा–ठाणाचौकी–मुरारी देवी की दयनीय स्थिति को सुधारा / सुदृढ़ीकरण जाए, विशेषकर 3 कि0मी0 कच्ची सड़क को पक्का किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
86.	मनरेगा के अन्तर्गत चौपाल विधानसभा क्षेत्र में किस–किस पंचायत में कितनी–कितनी राशि का क्या–क्या कार्य किया गया है इसकी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
87.	विधायक प्राथमिकता योजनाओं की बैठकों में प्रस्तुत की जाने वाली PPT presentation में एक अतिरिक्त कॉलम को जोड़ा जाए, जिस पर यह जानकारी दी जाए कि मदवार कितनी योजनाएं पूर्ण होने के बाद Handover की गई।	योजना विभाग
88.	चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों से अब तक किस–किस मद में कितना–कितना पैसा स्वीकृत हुआ है और वह पैसा कितना हुआ है। इसका पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए।	समस्त प्रशासनिक सचिव/ समस्त विभाग
89.	चौपाल क्षेत्र की मुख्य सड़क सेंज–देहा–चौपाल–पीड़जपुल के सुधारीकरण की डी.पी.आर. केन्द्र सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाए। इस कार्य के सुधारीकरण के कार्य को दो भागों में किया जाए। पहले भाग में पराला से देहा तक तथा दूसरे भाग में चौपाल से देहा तक, यदि इसमें कोई FCA होना है तो उपायुक्त शिमला इस बारे समय पर उचित कार्रवाई करे।	लोक निर्माण विभाग/ उपायुक्त शिमला
90.	सराहां से पंचकुला तक की सड़क के कार्य को CRIF में डाला जाए।	लोक निर्माण विभाग
91.	चौपाल क्षेत्र में 66 के.वी. पॉवर सप्लाई 30 कि0मी0 घने जंगल से होकर गुजरती है, जिससे लो–वोल्टेज की समस्या होती है इसे हल किया जाए।	HPSEBLtd.
92.	चौपाल क्षेत्र में आई.टी.आई. को दोबारा खोलने के लिए यह गणना की जाए कि +2 के बाद कितने विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं।	तकनीकी शिक्षा विभाग
93.	रोहडू क्षेत्र के सीमा महाविद्यालय में बी. एड. की कक्षाएं चलाने की अधिसूचना जारी की जाए।	शिक्षा विभाग
94.	नागरिक अस्पताल रोहडू के साथ–साथ प्रदेश के जिला अस्पतालों में नर्सो की कमी को दूर किया जाए।	स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा विभाग
95.	स्ट्रीट लाईटस की सुन्दरता के परीक्षण के लिए 7 स्ट्रीट लाईटस लगाई जाए।	HPSEBLtd./ M.C. Shimla

1.	मातृ शिशु अस्पताल नूरपुर के शेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु लगभग 3 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
2.	कांगड़ा जिला के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पंजाब राज्य की सीमा के साथ लगती है, जिससे वहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। इस अवैध खनन को रोकने के लिए पंजाब राज्य की सीमा के साथ लगते क्षेत्रों की demarcation करने बारे सचिव (उद्योग) उचित कार्रवाई करे तथा उस क्षेत्र में खनन का अधिकार क्षेत्र सम्बन्धित विधायक को प्रदान किया जाए, जिससे राज्य सरकार को royalty प्राप्त होगी।	उद्योग विभाग
3.	इन्दौरा के राम गोपाल मन्दिर डमटाल में 100 करोड़ रू0 के मुददे को हल किया जाए। इस सम्बन्ध में भाषा कला संस्कृति विभाग तथा उपायुक्त कांगड़ा, वन विभाग के साथ खैरों के पेड़ों की नीलामी हेतु पत्राचार करे। पेड़ों की नीलामी जल्दी करवाई जाए, ताकि राज्य को राजस्व प्राप्त हो।	भाषा कला एवं संस्कृति / वन विभाग / उपायुक्त कांगड़ा
4.	पुलिस पोस्ट इन्दौरा खोली जाए।	पुलिस विभाग
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित नशा क्लीनिक तथा नशा निवारण केन्द्रों की जाँच की जाए तथा गलत पाए जाने पर उन्हें बन्द कर दिया जाए। साथ ही नशा क्लीनिक तथा नशा निवारण केन्द्रों को खोलने की अनुमति सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक (DGP) की अनुमति अनिवार्य की जाए।	स्वास्थ्य / पुलिस विभाग / उपायुक्त कांगड़ा/ समस्त उपायुक्त / समस्त सम्बन्धित विभाग
6.	निर्वाचन क्षेत्र जसवां-प्रागपुर में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में कितनी सड़कों की FCA हुई है या नहीं हुई के कारणों सहित की सूची माननीय विधायक को शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए।	लोक निर्माण / वन विभाग
7.	निर्वाचन क्षेत्र जसवां-प्रागपुर में शूल खडड के पास करोड़ों रूपये की लगात से बने कौशल विकास निगम के भवन का सदुपयोग करने के लिए किसी अन्य विभाग को प्रदान किया जाए।	कौशल विकास निगम
8.	सलेटी अटल आदर्श विद्यालय के निर्माण के प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाए।	शिक्षा विभाग (उच्चतर /स्कूल)
9.	ज्वालामुखी में हैलीपोर्ट / हैलीपैड का निर्माण कार्य को उड़ान योजना में किया जाए।	पर्यटन विभाग
10.	प्रदेश में किसी भी सरकारी भवन निर्माण तथा पानी की स्कीमों को तैयार करने के प्राक्कलन (**budget estimate**) में ही बिजली तथा पानी के कम्पोनेंट को जोड़ा जाए तथा उसके बाद ही पूर्ण बजट प्राक्कलन (**integrated budget estimate**) तैयार किया जाए।	समस्त विभाग
11.	ज्वालामुखी विधान सभा क्षेत्र के जंदराह से लगड़ू वाया माढ़ तथा कुमकर कसेटी पुलों के अधूरे कार्य को एचरोचिज़ रोड़ के साथ शीघ्र निर्मित किया जाए। इन कार्यो के लिए बजट 2026-27 में धन का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण / योजना विभाग
12.	प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग **PMGSY-IV** की सड़कों में एक ठेकेदार को केवल 02 सड़कों के कार्य ही प्रदान करे।	लोक निर्माण विभाग
13.	निर्वाचन क्षेत्र सुलह में विद्यमान राय दी कूहल, जल शक्ति मण्डल थुरल का मुरम्मत कार्य / रख-रखाव PMKSY के अन्तर्गत किया जाए।	जल शक्ति विभाग
14.	सुलह विधान सभा क्षेत्र की कृपाल चन्द कूहल (लगभग 38 कि0मी0 लम्बी) का मुरम्मत कार्य / रख-रखाव के कार्य की डी.पी.आर. को स्वीकृत किया जाए।	जल शक्ति विभाग
15.	जल शक्ति विभाग की योजनाओं के आस-पास के क्षेत्र में खनन पर पूर्ण रोक लगाई जाए।	उद्योग / खनन विभाग
16.	बैजनाथ क्षेत्र की पपरोला-रक्कड़ सड़क की डी.पी.आर. को नाबार्ड से स्वीकृत करवाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
17.	प्रदेश में सभी सर्किट हाउसों तथा रैस्ट हाउसों को आउटसोर्स किया जाए।	समस्त उपायुक्त/ समस्त विभाग
18.	पालमपुर क्षेत्र के लोगों को मकान बनाने के लिए 2-2 किश्तें मिल चुकी हैं तथा अगली किश्तें कुछ नियम शर्तों के कारण नहीं मिल रही हैं इस बारे विभाग कार्रवाई करे।	ग्रामीण विकास विभाग /ESOMA Deptt.

***

(अनुबन्ध 'क')

वार्षिक बजट (2026–27) के लिए माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए माननीय विधायकों के साथ दिनांक 06 तथा 07 फरवरी, 2026 को आयोजित की गई बैठकों में माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, श्री भवानी सिंह पठानिया का स्वागत भाषण।

- माननीय मुख्य मन्त्री महोदय मंच पर मेरे साथ आसीन प्रदेश मन्त्री मण्डल के मान्य मंत्रीगण, अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, आज के सत्र में विभिन्न जिलों से उपस्थित जनप्रिय विधायकगण, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, प्रधान सचिव (योजना एवं वित्त), सभी–प्रशासनिक सचिव व विभागाध्यक्ष।

- मैं, हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में विधायक प्राथमिकताओं की इस बैठक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।

- प्रदेश सरकार की विधायक प्राथमिकताओं के लिए प्रति वर्ष दो दिवसीय बैठकों के आयोजन की यह परम्परा न केवल अद्धितीय है, बल्कि हमारे जीवंत लोकतन्त्र का एक सशक्त प्रमाण भी है। देश के बहुत कम राज्यों में ऐसी व्यवस्था है जहां स्वयं माननीय मुख्यमंत्री दो दिनों तक लगातार उपस्थित होकर इन बैठकों के माध्यम से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं और वहाँ की जन–आकांक्षाओं को सीधे जन–प्रतिनिधियों के माध्यम से सुनते हैं तथा माननीय विधायकों के व्यावहारिक अनुभव के आधार पर उनके निराकरण के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों / विभागाध्यक्षों को निर्देश भी देते हैं।

- माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सम्बन्धित क्षेत्र की प्राथमिकताओं के सही निर्धारण एवं उपलब्ध संसाधनों के आवंटन से प्रदेश का सर्वांगीण व समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

- मैं सभी माननीय विधायकों का धन्यवाद करता हूँ कि वे अपने–अपने क्षेत्रों की समस्याओं एवं विकास योजनाओं पर चर्चा के लिए इस बैठक में शामिल हुए हैं।

- मुझे पूर्ण विश्वास है की यह दो दिवसीय माननीय विधायकों के साथ संवाद हिमाचल प्रदेश के समावेशी विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

***

(अनुबन्ध 'ख')

वार्षिक बजट (2026–27) के लिए माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए माननीय विधायकों के साथ दिनांक 06 तथा 07 फरवरी, 2026 को आयोजित की गई बैठकों में माननीय मुख्य मन्त्री, श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु का उद्घाटन भाषण।

---

1. मैं, समस्त प्रतिभागियों का वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श हेतु आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वागत करता हूँ।

2. इस बैठक में होने वाले विचार विमर्श एवं परामर्श से हमें वित्त वर्ष 2026–27 के बजट की दिशा निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के त्वरित, समावेशी व सतत विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

3. हिमाचल प्रदेश की जनता के विश्वास व सहयोग से वर्तमान सरकार के तीन वर्ष लोक कल्याणकारी नीतियों, पारदर्शी शासन तथा व्यापक सुधारों से भरे रहे हैं। वर्तमान सरकार की नीतियों का लक्ष्य प्रदेश की अर्थवयवस्था को सुदृढ़ करना, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना, कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना तथा हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली, हरित ऊर्जा सम्पन्न व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना है।

4. 16वें वित्त आयोग (2026 से 2031 तक) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत राज्यों को मिलने वाली Revenue Deficit Grant (RDG) को लेकर उठाया गया कदम पहाड़ी राज्यों के लिए घातक है।

- वर्ष 1952 (प्रथम वित्त आयोग) से लेकर 15वें वित्त आयोग तक राज्यों की वित्तीय स्थिरता के लिए यह अनुदान निरन्तर मिलता रहा है, जिसे 16वें वित्त आयोग ने पहली बार बन्द किया है।

- 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए 37,199 करोड़ रूपये के राजस्व घाटा अनुदान (RDGs) की सिफारिश की थी। यहाँ तक की कोरोना काल के दौरान वित्त आयोग की रिपोर्ट में हुई देरी के बावजूद भी पिछली भाजपा सरकार के समय के दौरान अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 11,431 करोड़ रूपये की सहायता मिली थी इस अनुदान के बंद होने से हिमाचल जैसे छोटे और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्यों के लिए वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो गई है।

- 16वें वित्त आयोग / केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी तथा राज्य में चल रही कल्याणकारी योजनाओं व वेतन एवं पेंशन इत्यिादि पर भी विपरीत असर पड़ने की सम्भावना बढ़ गई है।

- परन्तु 16वें वित्त आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान ना दिए जाने के कारण जो क्षति हुई है उसे पूरा करने के लिए कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ–साथ

प्रदेश सरकार को राज्य का राजस्व बढ़ाने हेतु भविष्य में कड़े फैसले भी लेने पड़ सकते हैं।

- हम केन्द्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान (RDG) को बहाल करने व प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज देने की माँग करते हैं।

5. वर्ष 2023 में आई गम्भीर प्राकृतिक आपदा का सामना वर्तमान सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से सफतलतापूर्वक किया। इसी तरह साल 2025 में भी भारी बरसात और बादल फटने की घटनाओं से प्रदेश को जान–माल का भारी नुकसान हुआ। हमारी सरकार इस संकट की घड़ी में आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी रही और **Repair, Restoration, Relief और Rehabilitation के कार्यों को आप सभी के सहयोग से युद्धस्तर पर क्रियान्वित किया गया।**

6. हमारी सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए सात प्राथमिक क्षेत्रों को तय किया है जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, हरित ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और डाटा स्टोरेज शामिल हैं।

7. स्वस्थ हिमाचल की परिकलपना को महत्व देते हुए नागरिकों को उनके घर के समीप गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए Robotic Surgery, State Cancer Institute, DSA (Digital Subtraction Angiography), Advance Testing Labs, Bone Marrow Transplant Apheresis Unit सहित PET Scan, जैसी आधुनिक मशीनों की स्थापना की गई है।

8. हिमाचल **देश का पहला राज्य** है जो कि प्राकृतिक रूप से उगाए गये गेहूँ, जौ, मक्की, हल्दी एवं दूध पर सर्वाधिक सर्मथन मूल्य दे रहा है।

9. वर्तमान सरकार ने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के अपने संसाधनों से दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक 26 हजार 683 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया है।

10. प्रदेश के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सरकार प्रयासरत है। इसी क्रम में Wild Flower Hall Hotel की सम्पति के स्वामित्व का अधिकार प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त कर लिए हैं, जिससे राज्य को लगभग 401 करोड़ रूपये का वित्तीय लाभ हुआ है और प्रतिवर्ष 20 करोड़ रूपये की आय होने का अनुमान है।

11. राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से एक हजार मेगावॉट क्षमता की कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना में राज्य को मिलने वाली Royalty 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है। जिससे राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

12. औद्योगिक विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में राज्य में अनेक निवेशक हितैशी सुधारात्मक पहलें की गई हैं। सरकार के इन प्रयासों का परिणाम है कि केन्द्र सरकार

द्वारा संचालित **Business Reforms Action Plan-2024 में ''Top Achiever राज्य''** घोषित किया है।

13. हिमाचल प्रदेश डिजीटल नवाचारों में प्रगतिशील राज्यों के रूप में उभर रहा है। सरकारी काम–काज में Digitization और e-Filing प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार के Ministry of Electronics and Information Technology मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश को नागरिक केन्द्रित Digital सेवा वितरण में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए **''People First Integration Award''** से सम्मानित किया गया है।

14. वित्त वर्ष 2025–26 में प्रदेश सरकार ने RIDF के तहत 758.81 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है।

15. वर्ष 2025–26 के दौरान नाबार्ड से 713.87 करोड़ रूपये की 73 योजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं। इन स्वीकृत योजनाओं में 512.31 करोड़ रूपये की 55 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित हैं और 201.56 करोड़ रूपये की 18 विधायक प्राथमिकता योजनाएं जल शक्ति विभाग की हैं। इसके अतिरिक्त मार्च, 2026 तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है।

16. मेरा विशेषतः लोक निर्माण विभाग एवं जल शक्ति विभाग से आग्रह रहेगा कि नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए इन दोनों विभागों को तय बजट प्रावधान मु0 713.87 करोड़ रूपये के बजट का पूर्ण उपयोग करें और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति (Reimbursement) दावे दिनांक 15 मार्च, 2026 से पहले जमा करें।

17. मेरा सभी माननीय विधायकों से सादर अनुरोध है कि वह समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को अधिकतम 7 मिनट के भीतर ही सीमित रखें ताकि इस बैठक में उपस्थित अन्य विधायकों को भी अपने क्षेत्र के मुद्दे रखने का समान अवसर मिल सके। सभी माननीय विधायक अपने क्षेत्र के मुद्दे विस्तार से लिखित रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए मैं सभी प्रशासनिक सचिवों / विभागाध्यक्षों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देता हूँ। मैं मंचासीन माननीय मंत्रीगण / अध्यक्ष / उपाध्यक्ष से भी यह अनुरोध करता हूँ कि वह भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लिखित रूप में ही प्रस्तुत करें।

18. मैं, इन्हीं शब्दों के साथ अनुरोध करता हूँ कि बारी–बारी से सभी माननीय विधायक अपने बहुमूल्य विचार इस बैठक में प्रस्तुत करें।

***

माननीय विधायकों के साथ निर्धारित बैठकों की ***संशोधित जिलावार समय सारणी***

क्र0 सं0	जिले का नाम (निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या)	दिनांक	समय	
1.	1. ऊना (5) 2. हमीरपुर (5) 3. सिरमौर (5)	06-02-2026	पूर्वाहन् 10.30 से 1.30 बजे	मध्याहन भोज 1:30 से 2:00 बजे
2.	1. सोलन (5) 2. चम्बा (5) 3. बिलासपुर (4) 4. लाहौल व स्पीति(1) 5. किन्नौर (1)	06-02-2026	अपराहन् 2.00 से 5.00 बजे	
3.	1. कुल्लू (4) 2. मण्डी (10) 3. शिमला (4)*	07-02-2026	पूर्वाहन् 10.00 से 1.30 बजे	मध्याहन भोज 1:30 से 2:00 बजे
4.	1. शिमला (4)** 2. कांगड़ा (15)	07-02-2026	अपराहन् 2.00 से 5.00 बजे	

नोट : * शिमला पूर्वाहन सत्र में भाग लेने वाले माननीय विधायकों का निर्वाचन क्षेत्र (1) जुब्बल-कोटखाई, (2) कसुम्पटी, (3) चौपाल तथा (4) ठियोग

** शिमला अपराहन सत्र में भाग लेने वाले माननीय विधायकों का निर्वाचन क्षेत्र (1) शिमला ग्रामीण, (2) रामपुर, (3) रोहडू तथा (4) शिमला शहरी

***

माननीय मुख्य मन्त्री, हि0प्र0, की अध्यक्षता में विधायक प्राथमिकता की दो दिवसीय बैठकों में जिलावार / चुनाव क्षेत्रवार भाग लेने वाले माननीय मन्त्री एवं माननीय विधायकों का ब्यौरा ।

क्र. सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पदनाम
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
06–02–2026 (प्रातः 10:30 बजे से 1:30 बजे तक)				
1.	**ऊना**	1. चिन्तपूर्णी	श्री सुदर्शन सिंह बबलु	माननीय विधायक
		2. गगरेट	श्री राकेश कालिया	माननीय विधायक
		3. हरोली	श्री मुकेश अग्निहोत्री	माननीय उप मुख्यमंत्री, हि0प्र0
		4. ऊना	श्री सतपाल सिंह सत्ती	माननीय विधायक
		5. कुटलैहड़	श्री विवेक शर्मा	माननीय विधायक
2.	**हमीरपुर**	1. भोरंज	श्री सुरेश कुमार	माननीय विधायक
		2. सुजानपुर	कैप्टन रंजीत सिंह राणा	माननीय विधायक
		3. बड़सर	श्री ईन्द्र दत्त लखनपाल	माननीय विधायक
		4. नादौन	श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खू	माननीय मुख्य मन्त्री, हि0प्र0
3.	**सिरमौर**	1. पच्छाद	श्रीमति रीना कश्यप	माननीय विधायिका
		2. नाहन	श्री अजय सोलंकी	माननीय विधायक
		3. श्री रेणुका जी	श्री विनय कुमार	माननीय विधायक
		4. पावंटा साहिब	श्री सुख राम चौधरी	माननीय विधायक
		5. शिलाई	श्री हर्षवर्धन चौहान	माननीय मंत्री (उद्योग)
06–02–2026 (सांयः 2:00 बजे से 5:00 बजे तक)				
4.	**सोलन**	1. अर्की	श्री संजय अवस्थी	माननीय विधायक
		2. नालागढ़	श्री हरदीप सिंह बावा	माननीय विधायक
		3. दून	श्री राम कुमार	माननीय विधायक
		4. सोलन	डॉ0(कर्नल) धनी राम शॉंडिल	माननीय मंत्री (स्वास्थ्य)
		5. कसौली	श्री विनोद सुल्तानपुरी	माननीय विधायक
5.	**चम्बा**	1. चुराह	श्री हंस राज	माननीय विधायक
		2. भरमौर	डॉ0 जनक राज	माननीय विधायक
		3. चम्बा	श्री नीरज नैय्यर	माननीय विधायक
		4. डलहौजी	श्री डी0 एस0 ठाकुर	माननीय विधायक
6.	**बिलासपुर**	1. झण्डूता	श्री जीत राम कटवाल	माननीय विधायक
		2. घुमारवीं	श्री राजेश धर्माणी	माननीय मंत्री(तकनीकी शिक्षा)
		3. बिलासपुर	श्री त्रिलोक जमवाल	माननीय विधायक
		4. श्री नैनादेवी जी	श्री रणधीर शर्मा	माननीय विधायक
7.	**लाहौल–स्पीति**	1. लाहौल–स्पीति	कुमारी अनुराधा राणा	माननीय विधायिका
8.	**किन्नौर**	1. किन्नौर	श्री जगत सिंह नेगी	माननीय मंत्री (राजस्व)

क्र. सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पदनाम
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
07–02–2026 (प्रातः 10:00 बजे से 1:30 बजे तक)				
9.	**कुल्लू**	1. मनाली	श्री भुवनेश्वर गौड़	माननीय विधायक
		2. कुल्लू	श्री सुन्दर सिंह ठाकुर	माननीय विधायक
		3. बंजार	श्री सुरेन्द्र शौरी	माननीय विधायक
		4. आनी	श्री लोकेन्द्र कुमार	माननीय विधायक
10.	**मण्डी**	1. करसोग	श्री दीप राज	माननीय विधायक
		2. सुन्दरनगर	श्री राकेश कुमार	माननीय विधायक
		3. नाचन	श्री विनोद कुमार	माननीय विधायक
		4. द्रंग	श्री पूर्ण चन्द ठाकुर	माननीय विधायक
		5. जोगिन्द्रनगर	श्री प्रकाश राणा	माननीय विधायक
		6. धर्मपुर	श्री चन्द्र शेखर	माननीय विधायक
		7. मण्डी	श्री अनिल शर्मा	माननीय विधायक
		8. बल्ह	श्री इन्द्र सिंह	माननीय विधायक
		9. सरकाघाट	श्री दलीप ठाकुर	माननीय विधायक
11.	**शिमला**	1. जुब्बल–कोटखाई	श्री रोहित ठाकुर	माननीय मंत्री (शिक्षा)
		2. चौपाल	श्री बलबीर सिंह वर्मा	माननीय विधायक
		07–02–2026 (सांयः 2:00 बजे से 5:00 बजे तक)		
		3. शिमला–ग्रामीण	श्री विक्रमादित्य सिंह	माननीय मंत्री (लोक निर्माण)
		4. रोहड़ू	श्री मोहन लाल बराक्टा	माननीय विधायक
		5. शिमला–शहरी	श्री हरीश जनारथा	माननीय विधायक
12.	**कांगड़ा**	1. नूरपुर	श्री रणबीर सिंह	माननीय विधायक
		2. इन्दौरा	श्री मलेन्द्र राजन	माननीय विधायक
		3. फतेहपुर	श्री भवानी सिंह पठानिया	माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड
		4. ज्वाली	श्री चन्द्र कुमार	माननीय मंत्री (कृषि)
		5. जसवां–प्रागपुर	श्री बिक्रम सिंह	माननीय विधायक
		6. ज्वालामुखी	श्री संजय रतन	माननीय विधायक
		7. जयसिंहपुर	श्री यादविन्द्र गोमा	माननीय मंत्री(आयुष)
		8. सुलह	श्री विपिन सिंह परमार	माननीय विधायक
		9. नगरोटा	श्री आर0 एस0 बाली	माननीय उपाध्यक्ष (पर्यटन)
		10. कांगड़ा	श्री पवन काजल	माननीय विधायक
		11. शाहपुर	श्री केवल सिंह पठानिया	माननीय उप–मुख्य सचेतक, हिमाचल प्रदेश विधान सभा
		12. पालमपुर	श्री आशीष बुटेल	माननीय विधायक
		13. बैजनाथ	श्री किशोरी लाल	माननीय विधायक

***